जून 2024 में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का विश्लेषण

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली बैठक में संसद को संबोधित करना होता है। इस अभिभाषण में राष्ट्रपति द्वारा सरकार की प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित किया जाता है। इस नोट में जून 2024 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रमुख घोषणाओं (ग्रे रंग में) और घोषित पहलों की नवीनतम स्थिति का उल्लेख किया गया है।[1] आंकड़ों से संबंधित स्रोत एंडनोट्स में मौजूद हैं।

अर्थव्यवस्था एवं वित्त

आर्थिक वृद्धि: *10 वर्षों में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2021 से 2024 तक भारत सालाना औसतन 8% प्रतिशत की दर से बढ़ा है। आज भारत अकेले वैश्विक विकास में 15% योगदान दे रहा है। सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है।*

- USD में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी के मामले में भारत 2021-22 में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जो 2013-14 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था।[2] 2024 में भारत की जीडीपी लगभग 3.9 ट्रिलियन USD थी।[3]
- जीडीपी 2024-25 में 6.4% बढ़ने का अनुमान है (स्थिर कीमतों पर), जो 2023-24 (8.2%) की तुलना में सुस्त है।[4]

तालिका 1: 2024 में जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी

देश	जीडीपी (USD ट्रिलियन में)		प्रति व्यक्ति जीडीपी (USD में)	
	मूल्य	रैंक	मूल्य	रैंक
यूएसए	29.2	1	86,601	6
चीन	18.3	2	12,969	71
जर्मनी	4.7	3	55,521	16
जापान	4.1	4	32,859	37
भारत	3.9	5	2,698	140

नोट: रैंकिंग 188 देशों में से है। स्रोत: अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष; पीआरएस।

रेखाचित्र 1: स्थिर कीमतों पर जीडीपी वृद्धि (% में)

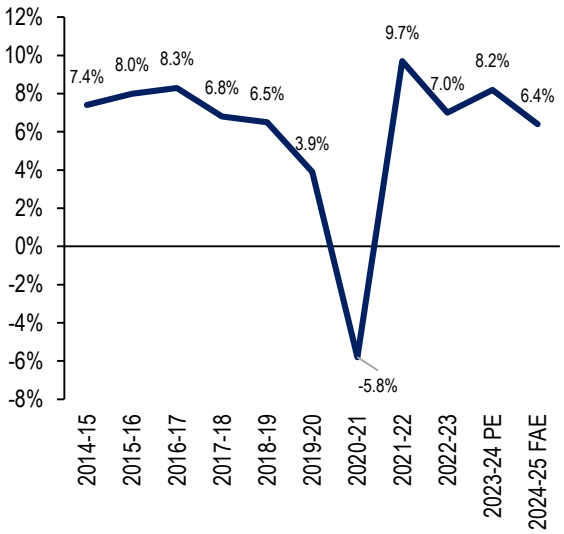

नोट: PE अनंतिम अनुमान है। FAE प्रथम अग्रिम अनुमान है। स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पीआरएस।

बैंकिंग क्षेत्र के सुधार: *10 वर्ष पहले भारत के बैंकिंग क्षेत्र को गिरावट से बचाने के लिए सरकार ने बैंकिंग सुधार किए और आईबीसी जैसे कानून बनाए। आज इन सुधारों ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में से एक बना दिया है। 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है जो पिछले वर्ष से 35% अधिक है। सरकारी बैंकों का एनपीए भी लगातार घट रहा है।*

- 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ 1.4 लाख करोड़ रुपए था, जो 2022-23 की तुलना में 35% अधिक है।[5] 2023-24 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल जमा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 59% थी।[6] 2013-14 में यह हिस्सेदारी 76% थी।[7]

शिरीन पजनू
shirin@prsindia.org
वैशाली धारीवाल
vaishali@prsindia.org
29 जनवरी, 2025

रेखाचित्र 2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध लाभ

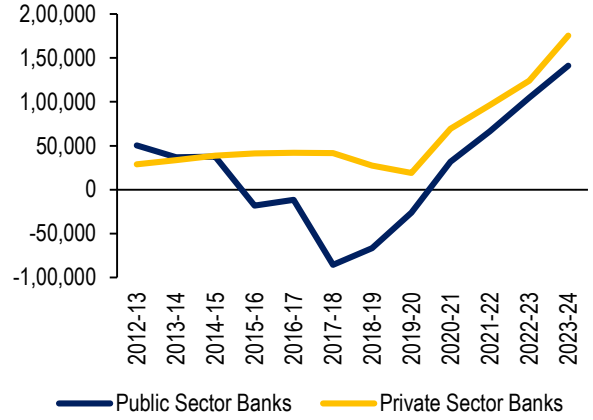

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक; पीआरएस।

रेखाचित्र 3: सकल अग्रिमों के % के रूप में सकल एनपीए

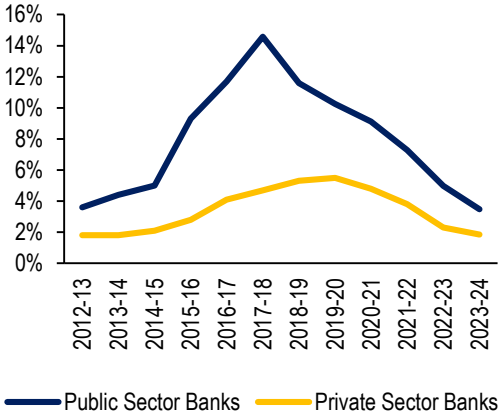

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक; पीआरएस।

- हाल के वर्षों में निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों के बैंकों के लिए सकल अग्रिमों के हिस्से के रूप में सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) कम हो गई है। एनपीए वे ऋण होते हैं जिन पर ब्याज और/या मूलधन का भुगतान 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है।[8] सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में सकल अग्रिमों के अनुपात के रूप में सकल एनपीए 2017-18 में 14.6% से घटकर 2023-24 में 3.5% हो गया है।[6] निजी बैंकों के लिए यह अनुपात 2017-18 में 4.7% से घटकर 2023-24 में 1.9% हो गया है।[6]
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 2023-24 में 15.5% था, जिसमें 2017-18 (11.7%) से लगातार सुधार है।[6,9] सीआरएआर संभावित नुकसान को सहने के लिए पर्याप्त पूंजी बरकरार रखने की बैंक की क्षमता को दर्शाता है। इसके परिचालन में जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, सीआरएआर को 9% से अधिक होना चाहिए।[6] 2023-24 में निजी क्षेत्र के बैंकों का सीआरएआर 17.8% था।[6]
- 2012-13 और 2021-22 के बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 3.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया (रेखाचित्र 5)।[10]

रेखाचित्र 4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी और जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात

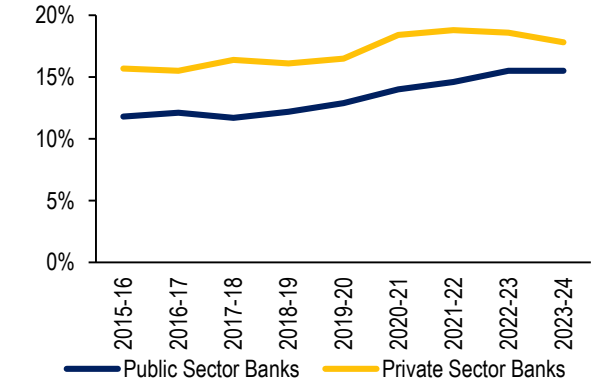

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक; पीआरएस।

रेखाचित्र 5: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश (करोड़ रुपए में)

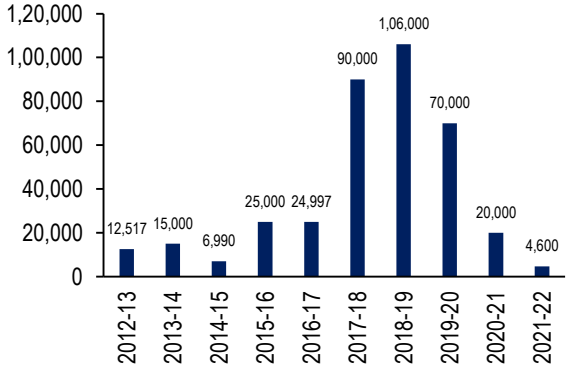

स्रोत: "बैंकिंग एनालिटिक्स", वित्तीय सेवा विभाग की वेबसाइट, 26 जनवरी, 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

- इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 (आईबीसी) कंपनियों और व्यक्तियों के बीच इनसॉल्वेंसी के रेज़ोल्यूशन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।[11] सितंबर 2024 तक आईबीसी के तहत 6,039 कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी की कार्यवाही बंद कर दी गई है।[12] इसमें से 1,068 मामलों के परिणामस्वरूप इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्लान (18%)

को मंजूरी मिल गई है।[12] अन्य 39% मामलों को निपटान या निकासी के कारण बंद कर दिया गया।[12] 44% मामलों में लिक्विडेशन हो गया है।[12] सितंबर 2024 तक में रेज़ोल्यूशन प्लान संबंधी मामलों के परिणामस्वरूप, लेनदार अपने 31% दावों को प्राप्त कर पाए।[12]

- कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन की कार्यवाही को खत्म करने में लगने वाली औसत अवधि 698 दिन रही है।[12] संहिता के अनुसार, कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया को 180 दिनों में पूरा किया जाना चाहिए (कुछ शर्तों के तहत 330 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)।[13] वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने आईबीसी के तहत मामलों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल की डेडिकेटेड बेंच बनाने का सुझाव दिया था।[14]

जीएसटी कलेक्शन: *अप्रैल महीने में पहली बार जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इससे राज्य आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए हैं।*

- अप्रैल 2017 में संसद ने जीएसटी लागू करने के लिए कानून पारित किया।[15] यह पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान अप्रत्यक्ष कर लगाता है। इसमें बिक्री कर और उत्पाद शुल्क जैसे कर शामिल हो गए।
- 2023-24 में जीएसटी कलेक्शन लगभग 20 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 6.1%) था जिसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल था।[16] जीडीपी के अनुपात के रूप में जीएसटी राजस्व वसूली पूर्व-जीएसटी व्यवस्था की तुलना में कम रही है। 2016-17 में जीएसटी के तहत शामिल करों से राजस्व जीडीपी का लगभग 6.3% था।[17] 15वें वित्त आयोग ने मध्यम अवधि (क्षतिपूर्ति उपकर से राजस्व का शुद्ध) पर 7% के जीएसटी-से-जीडीपी अनुपात की संभावना का अनुमान लगाया है।[18]

रेखाचित्र 6: जीडीपी के % के रूप में जीएसटी राजस्व

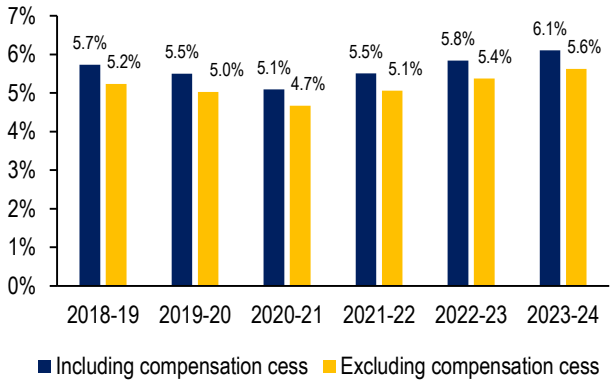

नोट: जीएसटी राजस्व केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जीएसटी आय को कहा जाता है। रेखाचित्र में 2017-18 को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि जीएसटी को वर्ष के कुछ भाग के लिए पेश किया गया था। स्रोत: जीएसटी नेटवर्क; केंद्रीय बजट दस्तावेज़; एमओएसपीआई; पीआरएस।

रक्षा एवं गृह मामले

रक्षा निर्यात: *पिछले दशक में हमारा रक्षा निर्यात 18 गुना से ज्यादा बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है।*

- 2023-24 में भारत ने 21,083 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात दर्ज किया।[19] 2013-14 में रक्षा निर्यात का मूल्य 686 करोड़ रुपए था।[20] रक्षा मंत्रालय ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा है।[21]
- प्रमुख रक्षा निर्यातों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ब्रह्मोस मिसाइलें, (ii) आकाश मिसाइल प्रणाली, (iii) बख्तरबंद वाहन, और (iv) बॉडी आर्मर्स।[22]
- निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) निर्यात के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को सरल बनाना, (ii) ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) की शुरुआत करना और (iii) रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा विदेशी कार्यालय खोलना।[21]

रेखाचित्र 7: रक्षा निर्यात में लगातार वृद्धि

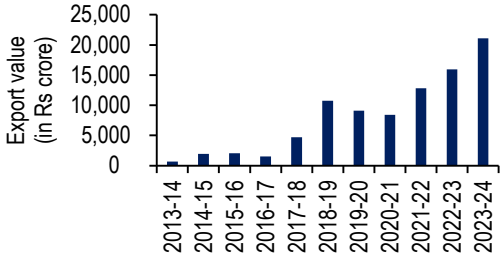

स्रोत: "डिफेंस एक्सपोर्ट्स राइज़ 23 टाइम्स", प्रेस सूचना ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय, 21 मई, 2023; अतारांकित प्रश्न संख्या 3094, लोकसभा, 25 मार्च 2022; "रक्षा निर्यात की स्थिति", प्रेस सूचना ब्यूरो, 13 दिसंबर, 2021; रक्षा उत्पादन विभाग डैशबोर्ड; पीआरएस।

रक्षा मैन्यूफैक्चरिंग: *भारत अब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा उपकरण बना रहा है। रक्षा बलों की कुल खरीद का लगभग 70% केवल भारतीय मैन्यूफैक्चरिंग से प्राप्त किया गया है। 40 से अधिक आयुध कारखानों को सात रक्षा क्षेत्र के उद्यमों में पुनर्गठित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उनकी क्षमता और दक्षता में सुधार हुआ है।*

- 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए रहा।[23] यह 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपए से 12% की वार्षिक वृद्धि है।[23] मंत्रालय ने 2029 तक तीन लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य रखा है।[23] अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि 65% रक्षा उपकरण अब भारत के भीतर निर्मित किए जा रहे हैं।[23]
- 2012-13 और 2021-22 के बीच सशस्त्र बलों के लिए खरीदे गए कुल रक्षा उपकरणों में से 40% रक्षा उपकरण विदेशी विक्रेताओं से प्राप्त किए गए थे।[24] इस अवधि के दौरान विदेशी स्रोतों से रक्षा उपकरणों की खरीद 5% की वार्षिक दर से बढ़ी, जबकि स्वदेशी खरीद 6% की वार्षिक दर से बढ़ी।[24] 2022-23 में 264 पूंजी खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें से लगभग 36% की विदेशी विक्रेताओं से खरीद की गई।[24]
- रक्षा उपकरणों की घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) रक्षा खरीद प्रक्रिया, 2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजी खरीद को प्राथमिकता देना, (ii) आयात प्रतिबंध के तहत कुछ वस्तुओं को रखने के लिए पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की अधिसूचना, (iii) लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, (iv) स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करना, और (v) उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित करना।[25] जनवरी 2025 तक 38,622 रक्षा वस्तुओं का आयात किया गया था। इनमें से 14,139 (37%) रक्षा वस्तुओं को घरेलू उत्पादन या स्वदेशीकरण के लिए मंजूरी दी गई है।[26]
- अक्टूबर 2021 में आयुध कारखानों को 41 इकाइयों के साथ सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में परिवर्तित कर दिया गया।[27,28] डीपीएसयू/अन्य पीएसयू ने 2023-24 में रक्षा उत्पादन में 79% योगदान दिया।[21] 2023-24 में कुल निर्यात में से डीपीएसयू ने लगभग 40% योगदान दिया।[21] 2023-24 में नए डीपीएसयूज़

द्वारा निर्यात 2022-23 में 82 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,977 करोड़ रुपए हो गया।[28] डीपीएसयू द्वारा निर्यात की गई कुछ प्रमुख वस्तुओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) गश्ती जहाज और हेलीकॉप्टर, (ii) इंजन, और (iii) हल्के वजन वाले रडार।[29] रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि डीपीएसयू द्वारा निर्मित उपकरणों के लिए आयात सामग्री अधिक है। उसने मंत्रालय को सुझाव दिया कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आत्मनिर्भर बनाने के उपाय किए जाएं।[24]

तालिका 2: डीपीएसयू का वित्तीय प्रदर्शन (करोड़ रुपए में)

डीपीएसयू	राजस्व		कर उपरांत लाभ	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड	4,652	7,222	73	559
बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड	4,876	4,663	271	605
एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	1,939	2,039	8	20
यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल)	2,391	2,821	51	425
इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	1,079	1,380	207	233
ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल)	955	279	19	-303
ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)	206	177	7	11

स्रोत: रिपोर्ट संख्या 4, रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी, दिसंबर 2024; पीआरएस।

वन रैंक वन पेंशन: *वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया है। इसके तहत अब तक 1,20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।*

- नवंबर 2015 में सरकार ने 1 जुलाई 2014 से प्रभावी लाभों के साथ वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने का निर्णय लिया। यह समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कर्मियों को एक समान पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान करता है। यह उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख की पर विचार किए बिना है।[30]
- दिसंबर 2024 तक 25 लाख से अधिक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।[21] 2015 में इसके कार्यान्वयन के बाद से नवंबर 2024 तक ओआरओपी पर 1.24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।[21] 2024-25 में रक्षा बजट का 23% पेंशन पर खर्च होने का अनुमान है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास: *सरकार ने पिछले 10 वर्षों में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए आवंटन में चार गुना से अधिक की वृद्धि की है। उत्तर-पूर्व के अशांत इलाकों में विकास को गति देकर वहां से चरणबद्ध तरीके से आफ्स्पा हटाने का काम भी चल रहा है।*

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आवंटन 2014-15 में 1,770 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 5,900 करोड़ रुपए हो गया। कई वर्षों में मंत्रालय द्वारा वास्तविक व्यय बजट अनुमान से कम था (रेखाचित्र 8)।
- इसके अतिरिक्त सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अपने सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% खर्च करना अनिवार्य है।[31] इसके तहत 2024-25 के बजट में क्षेत्र के लिए करीब एक लाख करोड़ रुपए आवंटित हैं।[32]

रेखाचित्र 8: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा धनराशि का उपयोग भिन्न-भिन्न

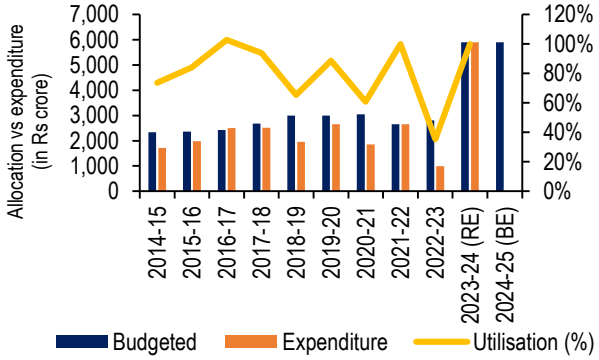

नोट: BE- बजट अनुमान। 2023-24 के वास्तविक आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।
स्रोत: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का विभिन्न वर्षों का व्यय बजट; पीआरएस।

- नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज (एनएलसीपीआर) एक ऐसी योजना थी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्त पोषित करती थी। इसे उत्तर-पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) में पुनर्गठित किया गया था।[33] 1999 से 2017 के दौरान एनएलसीपीआर योजना के तहत 1,635 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।[33] 2023 तक इनमें से 1,292 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं और इनमें 11 साल वर्ष का समय लग गया था।[33]
- गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि मंत्रालय के तहत विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वयन की धीमी गति और देरी से प्रभावित हुई हैं।[34] नीति आयोग (2018) के अनुसार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) खराब सड़क और रेल कनेक्टिविटी, (ii) उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग, (iii) पट्टे पर भूमि हस्तांतरित करने में कठिनाइयां, और (iv) सुरक्षा समस्याएं।[35]

तालिका 3: अगस्त 2024 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के चार राज्यों में आफ्स्पा लागू

राज्य	आफ्स्पा की स्थिति
असम	चार जिलों में लागू
अरुणाचल प्रदेश	तीन जिलों और एक अन्य जिले के तीन थाना क्षेत्रों में लागू
मणिपुर	19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रदेश में लागू
नगालैंड	आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में लागू

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 2303, लोकसभा, गृह मंत्रालय, 6 अगस्त, 2024; एस. ओ. 4921(ई), गृह मंत्रालय, भारत का राजपत्र, 14 नवंबर, 2024; पीआरएस।

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) एक्ट, आफ्स्पा, क्रमशः 2015 और 2018 में त्रिपुरा और मेघालय में पूरी तरह से वापस ले लिया गया था।[36] अन्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में, यह कुछ जिलों में लागू है (तालिका 3 देखें)। यह सिक्किम में लागू नहीं है, और इसे मिज़ोरम में कभी लागू नहीं किया गया है।[37,38]
- 2023 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिंसा की 243 घटनाएं दर्ज की गईं।[36] उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 77% हिंसक घटनाएं (187) मणिपुर में हुईं।[36] मार्च 2024 में 19 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में आफ्स्पा लागू कर दिया गया।[39] नवंबर 2024 में आफ्स्पा को अन्य छह पुलिस स्टेशन क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया, जिन्हें पहले शामिल नहीं किया गया था।[40] सरकार के मुताबिक, पिछले वर्ष मणिपुर में जातीय हिंसा में 258 लोग मारे गए।[41]

शरणार्थियों को नागरिकता: *सरकार ने सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देनी शुरू कर दी है। इस कानून ने विभाजन के कारण पीड़ित कई परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया है।*

- नागरिकता (संशोधन) बिल, 2019 दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था।[42] यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाता है। पात्रता उनके लिए तभी लागू होती है, अगर उन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है। यह व्यक्तियों के ऐसे समूह के लिए नैचुरलाइजेशन की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष करता है।[42]
- एक्ट के तहत नियमों को मार्च 2024 में अधिसूचित किया गया था।[43] नियमों की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाणपत्र का पहला सेट मई 2024 में जारी किया गया था। ये हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों में जारी किए गए थे।[44,45] पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से नागरिकता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे।[44,45]

कृषि एवं खाद्य सुरक्षा

एमएसपी: *सरकार ने खरीफ फसलों के एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है।*

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वह सुनिश्चित मूल्य है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें किसानों से कृषि उपज खरीदती हैं।[46] 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग (अध्यक्ष: डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन) ने सुझाव दिया था कि एमएसपी उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक हो।[47] 2018-19 के केंद्रीय बजट में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि वह ए2+एफएल लागत के आधार पर उत्पादन लागत का 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित करेगी।[48] ए2 फसल पैदा करने की लागत को दर्शाता है, और एफएल पारिवारिक श्रम की लागत को दर्शाता है।
- ए2+एफएल कुछ अन्य लागतों जैसे किराया और पूंजीगत संपत्तियों पर ब्याज का हिसाब नहीं रखता है। तालिका 4 में सी2 इन लागतों को शामिल करने के बाद उत्पादन की लागत है।

तालिका 4: 2024-25 में कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल में)

फसल	उत्पादन की लागत			ए2+एफएल के अनुपात के रूप में एमएसपी	सी2 के अनुपात के रूप में एमएसपी
	ए2+एफएल	सी2	एमएसपी		
धान	1,533	2,008	2,300	1.5	1.1
गेहूं	1,182	1,720	2,425	2	1.4
ज्वार	1,679	2,958	2,371	1.4	0.8
बाजरा	903	1,936	2,625	2.9	1.3
मक्का	1,135	1,863	2,225	2	1.2
मूंग	5,788	7,303	8,682	1.5	1.1
उड़द	4,883	6,496	7,400	1.5	1.1
सोयाबीन	3,261	4,291	4,892	1.5	1.1
कपास	4,747	6,230	7,121	1.5	1.1

स्रोत: कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 2024; पीआरएस।

किसानों की आय: *किसानों का खर्च कम होने की उम्मीद है। उनकी आय बढ़ने की उम्मीद है।*

- किसानों की आय में सुधार के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं लागू की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि- किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपए प्रदान करती है; (ii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- प्राकृतिक आपदा, कीटों और बीमारियों के चलते फसलों के नुकसान के मद्देनजर किसानों को बीमा प्रदान करती है; (iii) प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना- किसानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करती है; और (iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना- किसानों के लिए सुनिश्चित मूल्य और बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है।[49]
- 2012-13 में खेती करने वाले कृषि परिवार द्वारा फसल उत्पादन पर औसत मासिक व्यय 2,192 रुपए होने का अनुमान लगाया गया था।[50] 2018-19 में यह 5.3% की वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़कर 2,959 रुपए हो गया।[51]
- फसल उत्पादन से औसत मासिक आय 2018-19 में 3,932 रुपए थी, जो 2012-13 की तुलना में 4.1% की वार्षिक वृद्धि है (3,081 रुपए)।[50,51] 2018-19 में प्रति कृषि परिवार की औसत कुल मासिक आय 10,218 रुपए प्रति माह होने का अनुमान लगाया गया था, जो 2012-13 की तुलना में 8% की वार्षिक वृद्धि है (6,426 रुपए)।[50,51] इसमें अन्य स्रोतों से आय भी शामिल है जैसे मजदूरी और पशुपालन से कमाई (तालिका 5)।

तालिका 5: 2012-13 और 2018-19 में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय (रुपए में)

विषय	2012-13		2018-19		12-13 से 18-19 तक वार्षिक परिवर्तन
	राशि	% हिस्सा	राशि	% हिस्सा	
कुल मासिक आय	**6,426**	**-**	**10,218**	**-**	8.0%
इसमें से					
फसल उत्पादन से आय	3,081	48%	3,932*	38%	4.1%
पशुओं से आय	763	12%	1,582	15%	12.9%
मजदूरी से आय	2,071	32%	4,063	40%	11.9%
गैर कृषि कार्य से आय	512	8%	641	6%	3.8%

नोट: *जमीन को पट्टे पर देने से 134 रुपए की औसत मासिक आय शामिल है, जिसे अलग से दर्ज किया गया है। स्रोत: एंडनोट्स 50 और 51 का संदर्भ लें; पीआरएस।

किसानों को वित्तीय सहायता: *किसान अपने छोटे-छोटे खर्चों को पूरा कर सकें, इसके लिए पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं।*

- पीएम-किसान सम्मान निधि योजना योजना भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई थी।[52] योजना के तहत किसानों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए का हस्तांतरण प्रदान किया जाता है। यह हस्तांतरण किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से होता है। योजना की शुरुआत से जनवरी 2025 तक 18 किस्तों में किसानों को 3.5 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।[53]
- 2023-24 में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट आई (तालिका 6 देखें)। 2022-23 में किसानों को लाभ प्राप्त करने के लिए सक्रिय बैंक खातों के साथ भूमि विवरण और आधार प्रदान करना अनिवार्य हो गया।[54] इससे लाभार्थी खातों का डी-डुप्लीकेशन हो सकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।[55]

तालिका 6: पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी और वितरित राशि

वर्ष	कुल लाभार्थी (करोड़ में)	वितरित कुल राशि (करोड़ रुपए में)
2018-19	3.0	6,324
2019-20	8.8	48,741
2020-21	10.1	61,940
2021-22	10.8	67,147
2022-23	10.7	58,303
2023-24	9.9	61,879
2024-25*	9.3	20,067
कुल	**-**	**3,24,402**

नोट: 2024-25 से जुलाई, 2024 तक के आंकड़े। स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 1281, "पीएम किसान का कार्यान्वयन" लोकसभा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, 30 जुलाई 2024; पीआरएस।

दलहन और तिलहन के लिए आयात निर्भरता को कम करना: *सरकार दलहन और तिलहन के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को हर संभव मदद दे रही है।*

- 2022-23 में 165 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया, जो देश की कुल खाद्य तेल खपत का लगभग 57% है।[56] 2023-24 में पहले 11 महीनों में 143 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया, जो खाद्य तेलों की घरेलू मांग का 54% है।[56]
- खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन- ऑयल पाम (एनएमईओ-ओएस) घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए अक्टूबर 2024 में शुरू की गई एक पहल है।[56] इसे 2024-25 और 2030-31 के दौरान सात वर्ष की अवधि में लागू किया जाएगा। इसका प्रस्तावित परिव्यय 10,103 करोड़ रुपए है।[56] मिशन का लक्ष्य प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाना और

द्वितीयक तेल स्रोतों से तेल के संग्रह और निकासी दक्षता को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 2022-23 में 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 70 मिलियन टन करना है।[56]

- सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) लागू कर रही है जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और पोषक अनाज का उत्पादन बढ़ाना है।[57] यह मिशन किसानों से सीधे एमएसपी पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए पीएम-आशा के तहत मूल्य समर्थन योजना भी लागू कर रहा है।[57]

रेखाचित्र 9: दलहन का घरेलू उत्पादन और आयात (लाख टन में)

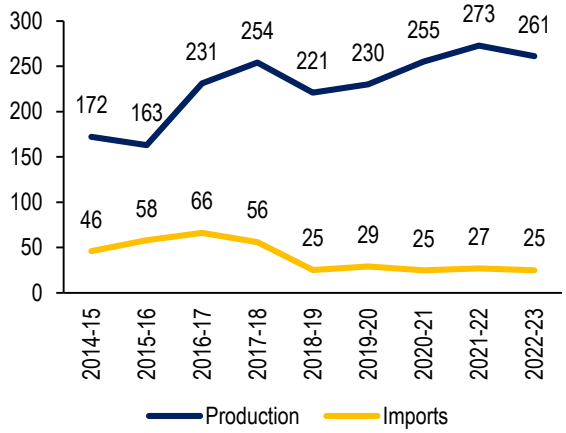

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; पीआरएस।

रेखाचित्र 10: तिलहनों का घरेलू उत्पादन, और खाद्य तेलों का आयात (लाख टन में)

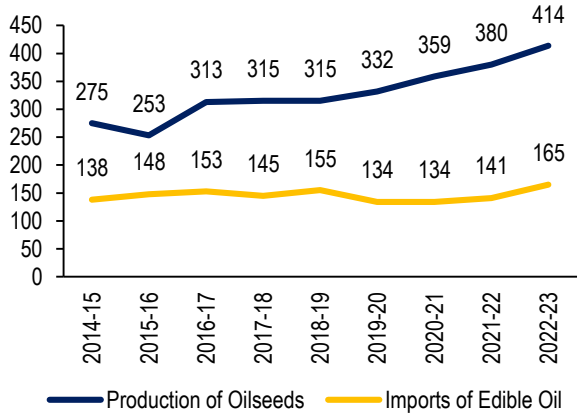

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, 2024; पीआरएस।

कृषि सहकारी संगठन: *सरकार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है।*

- एफपीओ कृषि उत्पादन और मार्केटिंग में पैमाने की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किसानों का एक समूह है।[58] केंद्र सरकार ने 2027-28 तक 10,000 नए एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2020 में एक योजना शुरू की।[58] इस योजना के तहत दिसंबर 2024 तक 9,411 एफपीओ का गठन किया गया है जिसमें 26 लाख किसान शामिल हैं।[59]

- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) किसानों को ऋण प्रदान करती हैं।[60] नवंबर 2024 तक देश में 1,01,524 पैक्स कार्यरत हैं।[61] पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में भी कार्य करते हैं। पीएमकेएसके के रूप में कार्य करने वाले पैक्स किसानों को एक ही स्थान पर उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण, कीटनाशक, मिट्टी/बीज परीक्षण सुविधाएं आदि प्रदान करते हैं।[62] दिसंबर 2024 तक 36,180 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रहे थे।[62]

- जून 2022 से केंद्र सरकार 67,930 चालू पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 2,516 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक परियोजना लागू कर रही है।[63] यह परियोजना कुशल संचालन के लिए राज्य और जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स को नाबार्ड से जोड़ती है। नवंबर 2024 तक 40,727 पैक्स को सॉफ्टवेयर में ऑनबोर्ड किया गया है।[63]

महिला सशक्तीकरण: *सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। अब तक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 30 हजार महिलाओं को कृषि सखी प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दे रही है।*

- एक लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है, जिसकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम एक लाख रुपए है और औसत मासिक आय कम से कम 10,000 रुपए है।[64] आय कम से कम चार कृषि मौसमों और/या व्यापार चक्रों तक बनी रहनी चाहिए।[64] केंद्रीय बजट 2024-25 में योजना के लक्ष्य को दो करोड़

व्यक्तियों से बढ़ाकर तीन करोड़ व्यक्तियों तक कर दिया गया था।[64] दिसंबर 2024 तक 1.15 करोड़ एसएचजी सदस्य लखपति दीदी बन गए हैं।[64]

- अगस्त 2023 में शुरू किया गया कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को पैरा-एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करता है।[65] पैरा-एक्सटेंशन वर्कर्स प्रशिक्षित पेशेवर हैं जो किसानों को उनकी कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नए ज्ञान को लागू करने में मदद करते हैं। जुलाई 2024 तक कुल 51,849 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य में प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 34,973 कृषि सखियों को अपना एग्रीकल्चर पैरा-एक्सटेंशन वर्कर प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुका है।[65]
- नवंबर 2024 में शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है ताकि वे कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को रेंटल सेवाएं प्रदान कर सकें।[66] यह योजना महिला नेतृत्व वाले एसएचजी को ड्रोन लागत का 80%, अधिकतम आठ लाख रुपए तक की सबसिडी प्रदान करती है।[66] इस योजना में 2023-24 और 2025-26 के बीच तीन वर्ष की अवधि के लिए 1,261 करोड़ रुपए का परिव्यय होने का अनुमान है।[67] 2024-25 में योजना ने 3,090 एसएचजी को 15,000 ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य रखा है।[66] उर्वरक कंपनियां, जो राज्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक हैं, ने 2023-24 में पहले 500 ड्रोन खरीदे और वितरित किए थे।[66]

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बीमा: *सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा और मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा।*

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में प्रति वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।[68,69] इसका लक्ष्य 12 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों) को कवर करना है।[68,69] जनवरी 2025 तक 36.4 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं।[70] 49% कार्ड महिलाओं को जारी किए गए हैं।[70] इन कार्डों का उपयोग अस्पताल में 6.8 करोड़ भर्तियों के लिए किया गया है।[70] जनवरी 2024 तक पैनल में शामिल अस्पतालों द्वारा 6.2 करोड़ दावे प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 5.8 करोड़ दावों का निपटान किया जा चुका है। मई 2023 तक योजना के तहत औसत दावा राशि 11,787 रुपए थी।[71]
- 2024-25 में इस योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।[72] 2022-23 में व्यय 6,185 करोड़ रुपए था।[72] स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने योजना के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का सुझाव दिया था।[73] 2018-19 और 2022-23 के बीच पांच वर्षों में, योजना के लिए धनराशि का उपयोग औसतन बजट अनुमान का लगभग 60% रहा।[74] स्वास्थ्य संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि योजना के लिए केंद्र के हिस्से के रूप में 6,000-7,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अपर्याप्त है।**Error! Bookmark not defined.** उसने यह भी कहा था कि योजना का कवरेज सीमित है। इसमें आउट-पेशेंट केयर, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और अस्पताल में भर्ती न होने पर होने वाला खर्च कवर नहीं किया जाता है।**Error! Bookmark not defined.**
- कैग (2023) ने कहा था कि कई राज्यों में सूचीबद्ध अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरणों और डॉक्टरों की कमी थी।[75] कुछ उपकरण काम नहीं करते पाए गए।[75] उसने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्री-ऑथराइजेशन अप्रूवल (बीमा कंपनी द्वारा इस बात की पुष्टि कि मरीज की पॉलिसी में अस्पताल में भर्ती को कवर किया जाता है) के लिए 40 लाख दावों में 12 घंटे के निर्दिष्ट समय से अधिक समय लगा।[75]

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान (2021-22) के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ पॉकेट एक्सपेंस (ओओपीई) 39% है।[76] 2014-15 में यह 63% था। आउट-ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का अर्थ यह है कि स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए परिवारों को कितना प्रत्यक्ष स्वास्थ्य व्यय करना पड़ता है।
- सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कवर करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया।[77] इसके द्वारा छह करोड़ नागरिकों के कवर होने की उम्मीद है।[77,78] दिसंबर 2024 तक 25 लाख व्यक्तियों को कार्ड जारी किए गए हैं।[79] 22,000 वरिष्ठ नागरिकों (70 वर्ष से अधिक) ने 40 करोड़ रुपए के उपचार का लाभ उठाया है।[79]

सस्ती दवाएं: *देश में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है।*

- जन औषधि योजना का उद्देश्य जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है।[80] इन फार्मेसियों को फार्मास्युटिकल उत्पादों की उनकी मासिक खरीद पर 20% की दर से प्रोत्साहन मिलता है।[80] प्रोत्साहन की सीमा 20,000 रुपए प्रति माह है।[80] सितंबर 2024 से मासिक प्रोत्साहन को 200 दवाओं के स्टॉकिंग मैंडेट से जोड़ा गया था।[81]
- सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या को 25,000 तक बढ़ाना है।[82] दिसंबर 2024 तक 14,320 जन औषधि केंद्र थे (मार्च 2026 के लक्ष्य का 57%)।[83]
- दिसंबर 2024 तक पिछले 10 वर्षों में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 6,462 करोड़ रुपए की दवा की बिक्री की गई है।[83] रसायन एवं उर्वरक से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने कहा था कि दवाओं की बिक्री की कुल मात्रा की तुलना में जन औषधि दवाओं की बिक्री की मात्रा बहुत कम है।[84] 2024-25 में फार्मास्यूटिकल्स का कुल सालाना कारोबार 4.2 लाख करोड़ रुपए था।[85] 2023-24 में जन औषधि केंद्रों की बिक्री 1,000 करोड़ रुपए रही।[82]

मेडिकल कॉलेजों की स्थापना: *पिछले 10 वर्षों में 15 नए एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं।*

- 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे।[86] नवंबर 2024 तक 780 मेडिकल कॉलेज हैं।[87]

तालिका 7: पिछले दशक में मेडिकल कॉलेजों और सीटों में वृद्धि

मेडिकल कॉलेज और सीटें	2013-14	2023-24
मेडिकल कॉलेजों की संख्या	387	780
स्नातक सीटों की संख्या	51,348	1,18,137
स्नातकोत्तर सीटों की संख्या	31,185	73,157

स्रोत: तारांकित प्रश्न संख्या 80, लोकसभा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 29 नवंबर, 2024; पीआरएस।

- कमिटी ऑन एस्टिमेट्स (2018) ने कहा था कि मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में से अधिकांश देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में स्थित हैं।[88] कुछ प्रमुख राज्यों में निम्न शामिल हैं: (i) महाराष्ट्र (10.2%), (ii) तमिलनाडु (10%), (iii) कर्नाटक (9.3%), (iv) तेलंगाना (8.3%), (v) गुजरात (5.2%), और (vi) केरल (4.3%)।[89]
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना देश के विभिन्न राज्यों में एम्स स्थापित करने पर केंद्रित है।[90] चरण 1 (2003-13) में छह एम्स जैसे संस्थानों को मंजूरी दी गई थी।[90] 2023 तक चरण 1 में स्वीकृत सभी छह एम्स पूरी तरह काम कर रहे हैं।[91]
- 2015 से 16 नए एम्स को मंजूरी दी गई है जिन्हें विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है।[90] ऐसे पांच संस्थानों में 90 ओपीडी डायग्नॉस्टिक और पैथोलॉजी सेवाएं शुरू हो गई हैं।[92] 2018 में कैग ने स्वीकृत नई परियोजनाओं में लागत और समय की अधिकता संबंधी मुद्दों को उजागर किया।[93] स्वास्थ्य से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा है कि सभी एम्स में स्वीकृत 5,527 फैकेल्टी पदों में से 2,161 रिक्त हैं (39% रिक्तियां)।[94]

शिक्षा

उच्च शिक्षण संस्थान: *पिछले 10 वर्षों में सात नए आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।*

- 2014 के बाद से सात आईआईटी, सात आईआईएम और 16 आईआईआईटी स्थापित किए गए हैं।[95] 2014-15 से 2021-22 के बीच 408 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।[96] लगभग 78% नए विश्वविद्यालय (सार्वजनिक और निजी) राज्यों द्वारा स्थापित किए गए थे।[96]
- मार्च 2023 तक केंद्र-वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में 34% फैकेल्टी पद खाली थे, जिनमें आईआईआईटी (54% रिक्ति), आईआईटी (39%), आईआईएम (31%), एनआईटी (29%) और केंद्रीय विश्वविद्यालय (33%) जैसे संस्थान शामिल हैं।[97]

रेखाचित्र 11: 2011-12 से उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि

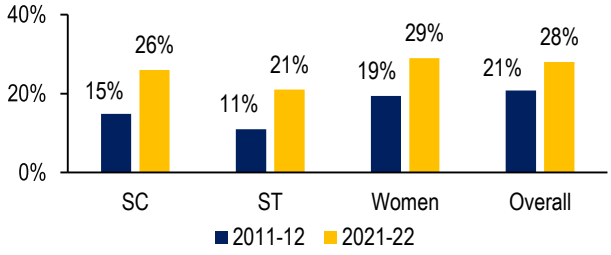

स्रोत: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2011-12 और 2021-22; पीआरएस।

- शिक्षा से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि उच्च शिक्षा में आदर्श विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 15:1 (प्रति विद्यार्थी पर एक शिक्षक) है।[97] 2021-22 तक उच्च शिक्षा में पीटीआर 23:1 था।
- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2021-22 में 28.4% था जो 2011-12 के स्तर (21%) से अधिक है।[96] जीईआर संबंधित आयु समूह की जनसंख्या की तुलना में एक विशिष्ट शिक्षा स्तर में नामांकित विद्यार्थियों के प्रतिशत को मापता है।[96] सामाजिक समूहों में नामांकन स्तर में वृद्धि हुई है (रेखाचित्र 11)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक बढ़ाना है।[95]
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्नातक स्तर की डिग्री या उससे उच्च शिक्षा वाले व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2022 में 29% थी।[98] रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में सभी नियोजित स्नातकों में से 53% कम कुशल नौकरियों में लगे हुए थे। उनमें से 27% उच्च-कुशल नौकरियों में लगे हुए थे।[98]
- 2020-21 में भारत के अनुसंधान व्यय में विश्वविद्यालयों की हिस्सेदारी 9% थी।[99] भारत के आर्थिक सर्वेक्षण (2017-18) में पाया गया कि भारत में सरकारी अनुसंधान व्यय विशेष सरकारी विभागों में केंद्रित है।[100] सर्वेक्षण में शिक्षण और अनुसंधान के बीच अंतर को पाटने के लिए विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से जोड़ने का सुझाव दिया गया।[100]

क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यक्रम: *अब एनईपी की शुरुआत के साथ विद्यार्थी भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं।*

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) में सुझाव दिया गया है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम पेश करें।[101,102] अप्रैल 2022 तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों को छह भाषाओं में 26 पाठ्यक्रम संचालित करने को मंजूरी दे दी।[101] उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 2,000 से अधिक लेक्चर्स और 160 पुस्तकों का अनुवाद, और (ii) 13 भाषाओं में इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करना।[101]

नकल विरोधी कानून: *संसद ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के विरुद्ध भी सख्त कानून बनाया है। सरकार परीक्षा संबंधी निकायों, उनकी कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं में बड़े सुधारों की दिशा में काम कर रही है।*

- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024 को फरवरी 2024 में पारित किया गया था।[103] एक्ट सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने का प्रयास करता है। इनमें निम्नलिखित द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं: (i) संघ लोक सेवा आयोग, (ii) कर्मचारी चयन आयोग, (iii) रेलवे भर्ती बोर्ड, और (iv) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। अनुचित साधनों में परीक्षा सामग्री लीक करना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना और लाभ के लिए बाधा डालना या नकल करना शामिल है। झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने भी अपने संबंधित नकल विरोधी कानून पारित किए हैं।[104,105,106]

सामाजिक न्याय

गरीबी उन्मूलन: *25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।*

- गरीबी के लिए अलग-अलग उपाय हैं। गरीबी को आय स्तर के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विश्व बैंक के अनुसार, भारत में अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (प्रति दिन 2.15 USD) से नीचे कमाई करने वाली आबादी का प्रतिशत 2015 में 18.7% से घटकर 2021 में 12.9% हो गया।[107] 2004 में इस पैमाने पर 40.6% व्यक्तियों के गरीब होने का अनुमान है।[107]
- बहुआयामी गरीबी माप का एक और तरीका है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और आवास जैसे विभिन्न संकेतकों में अभाव का आकलन करता है।[108] संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऐसे 10 संकेतकों पर विचार करता है।[108] इसके अनुसार, भारत में 2015-16 (37 करोड़ बहुआयामी गरीब व्यक्ति) और 2020-21 (23 करोड़ बहुआयामी गरीब व्यक्ति) के बीच 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया।[108] ये अनुमान क्रमशः 2015-16 और 2019-21 की अवधि में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित हैं।[108]

तालिका 8: भारत की जनसंख्या का प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से गरीब है

वर्ष	यूएनडीपी का बहुआयामी गरीबी सूचकांक	नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक
2005-06	55%	55%
2015-16	28%	25%
2019-21	16%	15%

स्रोत: 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी, चर्चा पत्र, नीति आयोग, 12 जनवरी 2024; वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, यूएनडीपी; पीआरएस।

- वैश्विक सूचकांक के समान, नीति आयोग ने एक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को परिभाषित किया है।[109] यह सूचकांक वैश्विक सूचकांक के अंतर्गत आने वाले संकेतकों के अलावा दो और संकेतकों पर विचार करता है।[109] ये मातृ स्वास्थ्य और बैंक खातों तक पहुंच से संबंधित हैं।[109] राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, 2015-16 और 2020-21 के बीच 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया।[110]
- 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र में अनुमान लगाया गया कि 2013-14 और 2022-23 के बीच नौ वर्षों में 24.8 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया।[109] इसने 2015-16 और 2019-21 की अवधि के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर ये अनुमान लगाए।[109]

आदिवासी कल्याण: *24,000 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली पीएम जनमन जैसी योजना सबसे पिछड़े आदिवासी समुदायों के विकास का साधन बन रही है।*

- नवंबर 2023 में सरकार ने 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया। ये समूह 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की लगभग तीन लाख दूरदराज की बस्तियों में रहते हैं।[111] यह बुनियादी सुविधाएं प्रदान

करने पर केंद्रित है जैसे: (i) सुरक्षित आवास, (ii) स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, (iii) शिक्षा तक बेहतर पहुंच, (iv) स्वास्थ्य और पोषण, (v) बिजली, और (vi) सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी (तालिका 9)।[111,112] यह योजना 2025-26 तक चालू रहेगी।[111] योजना का कुल परिव्यय 24,104 करोड़ रुपए है जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 15,336 करोड़ रुपए है।[111] उद्देश्यों को 11 पहलों के माध्यम से पूरा करने की योजना है।

तालिका 9: जुलाई 2024 तक पीएम-जनमन योजना के तहत प्रगति

परियोजनाएं	लक्ष्य	जुलाई 2024 तक स्वीकृत
पक्के मकानों का प्रावधान	4.9 लाख घर	2.26 लाख घर
संपर्क मार्ग	8,000 कि.मी	2,746 कि.मी
मोबाइल चिकित्सा इकाइयां	1,000 इकाइयां	578 इकाइयां
पाइप से जलापूर्ति	4.9 लाख नल कनेक्शन	2.9 लाख नल कनेक्शन
आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण	2,500 केंद्र	1,050 केंद्र (520 चालू)
छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन	500 छात्रावास	100 छात्रावास
अविद्युतीकृत घरों का ऊर्जाकरण	2.35 लाख	1.23 लाख घर
सौर ऑफ-ग्रिड विद्युत प्रणाली	एक लाख परिवार	5,067 घर
बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	1,500 केंद्र	823 केंद्र
वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके)	500 केंद्र	501 केंद्र

स्रोत: "कैबिनेट ने प्रधानमंत्री के जनजातीय और आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी", प्रेस सूचना ब्यूरो, 29 नवंबर, 2023; "कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी", प्रेस सूचना ब्यूरो, 18 सितंबर, 2024; अतारांकित प्रश्न संख्या 488, लोकसभा, जनजातीय कार्य मंत्रालय, 25 जुलाई, 2024; पीआरएस।

विकलांगों को सहायता: *सरकार दिव्यांग भाई-बहनों के लिए किफायती स्वदेशी सहायक उपकरण विकसित कर रही है। पीएम दिव्याशा केंद्रों का भी देश के सभी हिस्सों में विस्तार किया जा रहा है।*

- सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद या फ़िटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने वाली योजना (एडिप) का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने हेतु सहायक सहायता और उपकरण प्रदान करना है (जैसे वॉकिंग स्टिक और हियरिंग एड्स)।[113, 114] 40% और उससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र वाले दिव्यांगजन इस योजना के तहत पात्र हैं।[115] दिसंबर 2024 तक पिछले 10 वर्षों में 29 लाख दिव्यांगजनों को 2,080 करोड़ रुपए की संचयी लागत पर सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं।[113,116]
- भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) एडिप योजना की एक कार्यान्वयन एजेंसी है।[117] यह पीएम दिव्याशा केंद्रों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को मुफ्त सहायता, उपकरण और सहायक उपकरण प्रदान करता है।[118] अक्टूबर 2024 तक 65 पीएम दिव्याशा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।[119] सरकार का लक्ष्य 2026 तक 300 दिव्याशा केंद्र स्थापित करना है।[120]

उद्योग

लॉजिस्टिक्स की लागत: *सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है।*

- केंद्र सरकार द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत 2015-2016 में जीडीपी के 13% से घटकर 2021-22 में जीडीपी का 7.8-9% हो गई है।[121] राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 का लक्ष्य है: (i) भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को वैश्विक बेंचमार्क (जीडीपी का 8-10%) तक कम करना, और (ii) विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) में भारत की रैंकिंग में सुधार करके 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल करना।[122] 2023 तक भारत एलपीआई सूचकांक पर 38वें स्थान पर है।[123]

- राष्ट्रीय नीति के तहत, लॉजिस्टिक्स में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना विकसित की गई है।[124] योजना के तहत कुछ कार्य क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम का निर्माण; (ii) भौतिक संपत्तियों का मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता मानकों की बेंचमार्किंग; (iii) मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण; (iv) सेवा सुधार ढांचा; और (v) कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय योजनाएं। अक्टूबर 2024 तक 26 राज्यों ने अपनी स्वयं की लॉजिस्टिक नीतियां भी जारी कर दी हैं।[124]

पीएलआई योजनाएं: *पीएलआई योजनाओं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने में योगदान दिया है।*

- 2020 से केंद्र सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है (तालिका 10)।[125] ये योजनाएं किसी दिए गए आधार वर्ष के दौरान भारत में निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। इन योजनाओं का अनुमानित बजटीय परिव्यय 1.97 लाख करोड़ रुपए है। इनका लक्ष्य पांच वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन हासिल करना है।[126]
- पीएलआई योजनाओं के तहत 764 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।[127] अगस्त 2024 तक 1.46 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है, और लगभग 9.5 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं।
- इन योजनाओं से अगस्त 2024 तक 12.5 लाख करोड़ रुपए का वृद्धिशील उत्पादन हुआ है, जिसमें चार लाख करोड़ रुपए का निर्यात भी शामिल है।[127]

तालिका 10: पीएलआई योजनाओं पर बजटीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र/उत्पाद	अनुमानित परिव्यय	2022-23 वास्तविक	2023-24 संअ	2024-25 बअ
ऑटो घटक और ऑटोमोबाइल	25,938	6	484	3,500
ड्रोन	120	30	33	57
एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी	18,100	2	12	250
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर	57,890	1,655	4,560	6,200
खाद्य प्रसंस्करण	10,900	490	1,150	1,444
विशेष इस्पात	6,322	0	2	246
फार्मास्युटिकल मैन्यूफैक्चरिंग	15,000	655	1,632	2,000
मुख्य आरंभिक सामग्रियां (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (थोक औषधियां)	6,940	6	16	58
चिकित्सा उपकरण	3,420	12	48	85
उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल*	24,000	-	-	-
दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद	12,195	39	515	1,806
कपड़ा और परिधान	10,683	7	5	45
सफेद वस्तुएं	6,238	4	65	298
कुल	**1,97,746**	**3,657**	**8,007**	**15,973**

नोट: *अगस्त 2024 में नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि प्रदान की गई मैन्यूफैक्चरिंग क्षमताएं प्रारंभिक अवधि में हैं, इसलिए आज तक कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।[128] संअ का मतलब संशोधित अनुमान है, बअ का मतलब बजटीय अनुमान है। स्रोत: विभिन्न वर्षों के व्यय बजट दस्तावेज़, केंद्रीय बजट; पीआरएस।

सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग: *पूर्वोत्तर भी मेड इन इंडिया चिप्स का हब बनेगा।*

- 2021 में प्रारंभ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम घरेलू स्तर पर निर्मित सेमीकंडक्टर वस्तुओं जैसे एकीकृत सर्किट (आईसी) और चिपसेट की बिक्री पर 4-6% का प्रोत्साहन प्रदान करता है।[129] इस कार्यक्रम को कुल 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी।[129]
- कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली पांच सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को मंजूरी दी गई है।[130] इनमें से एक इकाई असम के मोरीगांव में होगी। इस इकाई में करीब 27,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।[131] इससे लगभग 15,000 प्रत्यक्ष और 13,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने का अनुमान है।[131]

इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित हाइड्रोजन को अपनाना: *सनराइज क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है - ईवी और हरित हाइड्रोजन।*

- इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख पहलों में निम्न शामिल हैं: (i) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और मैन्यूफैक्चर करना (फेम I और II)- इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सबसिडी देने की योजना, और (ii) इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के लिए ऑटोमोबाइल घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं।[132,133]
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और मैन्यूफैक्चर करना (फेम-I) के पहले चरण के तहत लगभग 2.8 लाख ईवी (दो, तीन और चार पहिया वाहन) और 425 ई-बसों को प्रोत्साहित किया गया था।[134] फेम-II योजना के तहत, 16.7 लाख ईवी और 4,853 ई-बसों को प्रोत्साहन दिया गया है।[135]

तालिका 11: 2015-16 और 2021-22 के बीच फेम के तहत 100% धनराशि उपयोग

वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपए में)	उपयोग (करोड़ रुपए में)
	फेम I	
2015-16	75	75
2016-17	144	144
2017-18	165	165
2018-19	145	145
कुल	**529**	**529**
	फेम II	
2019-20	500	500
2020-21	318	318
2021-22	800	800
2022-23	2,898	2,403
2023-24	5,172	1,981*
कुल	**9,688**	**6,002**

नोट: *आंकड़े 31 जनवरी 2024 तक। स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 105, राज्यसभा, भारी उद्योग मंत्रालय, 2 फरवरी, 2024; प्रेस सूचना ब्यूरो, भारी उद्योग मंत्रालय, 11 जुलाई, 2022; पीआरएस।

तालिका 12: दिसंबर 2024 तक भारत में दोपहिया और चार पहिया ईवी

श्रेणी	इलेक्ट्रिक वाहन	आईसीई वाहन	कुल वाहन	ईवी अपनाने की दर
दोपहिया	28,55,015	27,96,24,745	28,24,79,760	1.01%
चार पहिया	2,57,169	8,12,79,805	8,15,36,974	0.32%

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 2303, लोकसभा, भारी उद्योग मंत्रालय, 10 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

- हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था।[136] मिशन के लिए कुल अनुमानित परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है।[136] इसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष पांच मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है।[136] 2030 तक मिशन के तहत आठ लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है, जिससे लगभग छह लाख नौकरियां पैदा होंगी।[137]
- दिसंबर 2024 तक 0.4 मिलियन टन प्रति वर्ष की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और 3,000 मेगावाट प्रति वर्ष की इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता आवंटित की गई है।[138]

स्टार्टअप्स को सशक्त करना: *आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इको-सिस्टम बन गया है।*

- स्टार्ट-अप इंडिया योजना जनवरी 2016 में शुरू की गई थी।[139] जनवरी 2025 तक लगभग 1.6 लाख स्टार्टअप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।[140] अक्टूबर 2024 तक, इन स्टार्ट-अप्स ने 16.6 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की थीं, जो कि उनका खुद का दावा है।[141] अधिकांश नौकरियां आईटी सेवाओं, शिक्षा और निर्माण के क्षेत्र में सृजित हुईं।[141] मई 2023 तक भारत में 341 बिलियन USD के संचयी मूल्यांकन के साथ 108 यूनिकॉर्न (एक बिलियन USD से अधिक मूल्य) थे।[142]
- स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने की योजनाएं शामिल हैं (तालिका 13)। 2016 और 2024 के बीच इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स को उनके निगमन के पहले सात वर्षों में से लगातार तीन वर्षों तक मुनाफे पर कर छूट प्रदान की जाती है।[142] वाणिज्य और उद्योग से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि मार्च 2023 तक केवल 10% पंजीकृत स्टार्टअप्स (10,165) ने कर छूट की मांग की है।[142] इसके अलावा केवल 1% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप (1,173) को अंतर-मंत्रिस्तरीय बोर्ड से पात्रता का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।[142] कमिटी ने सुझाव दिया था कि पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के मानदंडों में ढील दी जानी चाहिए ताकि अधिक स्टार्टअप्स कर लाभ प्राप्त कर सकें।[142] उसने कहा कि 75% आवेदनों को दोबारा जमा करने को कहा गया था जो प्रक्रिया में अस्पष्टता का संकेत हो सकता है।[142]

तालिका 13: स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कार्यक्रम

योजना	उद्देश्य	कॉरपस	प्रगति
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना	अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता	945 करोड़ रुपए	अक्टूबर 2024 तक 903 करोड़ रुपए की स्वीकृत फंडिंग के साथ 213 इनक्यूबेटरों का चयन किया गया है।[143] इन स्वीकृत इनक्यूबेटरों ने 2,490 स्टार्टअप का चयन किया है और उन्हें 454 करोड़ रुपए की फंडिंग की मंजूरी दी है।[143]
स्टार्टअप्स योजना के लिए फंड ऑफ फंड्स	प्रारंभिक चरण, सीड चरण और विकास चरण के लिए पूंजी उपलब्धता	10,000 करोड़ रुपए	सितंबर 2024 तक 141 निवेश कोषों के लिए 10,913 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धताएं की गई हैं।[144] इन इन्वेस्टमेंट फंड्स ने 1,120 स्टार्टअप्स में 19,992 करोड़ रुपए का निवेश किया है।[144]

स्रोत: 20 जनवरी, 2025 को एक्सेस की गई स्टार्ट अप इंडिया की वेबसाइट; अतारांकित प्रश्न संख्या 2916, राज्यसभा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 20 दिसंबर 2024; "स्टार्ट-अप्स योजना के लिए फंड ऑफ फंड्स ", 28 जनवरी, 2024 को एक्सेस की गई सिडबी की वेबसाइट; पीआरएस।

इंफ्रास्ट्रक्चर एवं परिवहन

विमानन: *भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। अप्रैल 2014 में भारत में केवल 209 एयरलाइन मार्ग थे। अप्रैल 2024 तक यह बढ़कर 605 हो गए हैं। विमानन मार्गों में इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा टियर-2 और टियर-3 शहरों को हुआ है।*

- देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2024 में 157 हो गई है।[145] 2013-14 और 2023-24 के बीच घरेलू यात्री यातायात 7% की वार्षिक औसत दर से बढ़ा।[146] इसी अवधि के दौरान घरेलू कार्गो यातायात ने 4% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की।[146]
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) नवंबर 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मार्गों की पहचान करके और ऑपरेटरों को सबसिडी और विशिष्टता प्रदान करके टियर-2 और टियर-3 शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ाना है।[145] उड़ान के तहत 948 मार्ग स्वीकृत किए गए हैं।[145] दिसंबर 2024 तक, 87 हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 619 मार्गों का संचालन किया जा चुका है।[147] उड़ान के तहत 13 एयरलाइनों ने परिचालन शुरू किया है।[148] उड़ान मार्गों के संचालन में देरी के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भूमि की अनुपलब्धता, (ii) हवाई अड्डों पर तकनीकी और परिचालन संबंधी बाधाएं, (iii) उपयुक्त विमानों की अनुपलब्धता, और (iv) परमिट संबंधी मुद्दे।[149]

बुलेट ट्रेन: *अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई-स्पीड रेल इकोसिस्टम पर भी काम तेजी से चल रहा है।*

- मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना 2017 में शुरू की गई थी।[150] परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 1.1 लाख करोड़ रुपए है।[150] परियोजना की लंबाई 12 स्टेशनों के साथ 508 किमी है, जो गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है।[150] इस परियोजना को जापान सरकार से सहायता मिल रही है।[151]
- नवंबर 2024 तक परियोजना की भौतिक प्रगति 49% होने का अनुमान है।[152] परियोजना के लिए 100% भूमि (1,390 हेक्टेयर) का अधिग्रहण किया जा चुका है।[151] दिसंबर 2024 तक परियोजना पर 70,051 करोड़ रुपए (स्वीकृत राशि का 65%) खर्च किए जा चुके हैं।[152]
- मूल रूप से परिचालन दिसंबर 2023 तक शुरू होने की उम्मीद थी।[152] अब इसके अगस्त 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है।[152]

राजमार्ग: *राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति दोगुनी से भी अधिक हो गई है।*

- जनवरी 2025 तक कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 1.46 लाख किमी है।[153] यह 2014 (91,287 किमी) की तुलना में 60% की वृद्धि है।[153] अप्रैल 2014 और मार्च 2022 के बीच 49,339 किमी राज्य सड़कों (राज्य राजमार्गों सहित) को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया था।[154,155]
- 2016-17 से निर्माण की गति 20 किमी/दिन से अधिक रही है (रेखाचित्र 12)।[153] 2014-15 में यह 12 किमी/दिन थी। 2020-21 में यह बढ़कर 37 किमी/दिन हो गया।[153] दिसंबर 2024 तक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह 21 किमी/दिन होने का अनुमान है।[153]
- 2024-25 में सरकार ने 10,400 किलोमीटर का निर्माण लक्ष्य रखा है।[156] नवंबर 2024 तक उसने लक्ष्य का लगभग 46% हासिल कर लिया है।[156] 2020-21 को छोड़कर मंत्रालय ने पिछले पांच वर्षों में अपने निर्माण लक्ष्यों को पूरा नहीं किया (रेखाचित्र 12)।

  राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने की चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, (ii) अतिक्रमण हटाना, और (iii) पर्यावरण/वन/वन्यजीव मंजूरी।[157] मार्च 2024 तक 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली 1,093 चालू सड़क परियोजनाओं में से 399 परियोजनाओं में देरी हुई (36%)।[158]

रेखाचित्र 12: लक्षित बनाम निर्मित एनएच (किमी में)

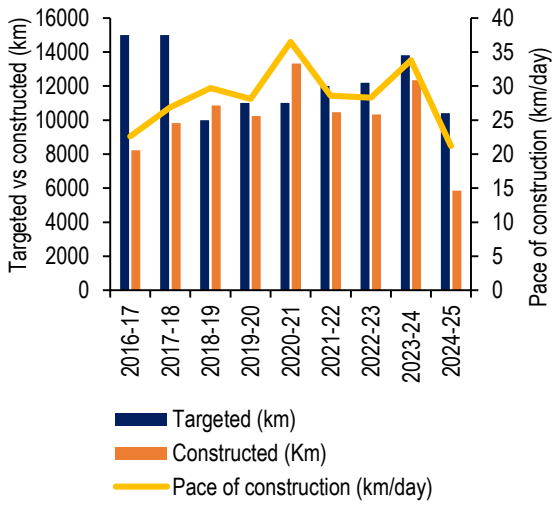

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 3947, लोकसभा, 19 दिसंबर, 2024; अतारांकित प्रश्न संख्या 3300, राज्यसभा, 22 जुलाई 2019; वर्षांत समीक्षा 2024- सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो; 9 जनवरी, 2025; "फोर लेनिंग ऑफ हाइवेज़ ", प्रेस सूचना ब्यूरो, 3 अगस्त 2023; पीआरएस।

अंतर्देशीय जलमार्ग: *पहली बार अंतर्देशीय जलमार्ग पर इतने बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ है। इस पहल से पूर्वोत्तर को काफी फायदा होगा।*

- देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट, 2016 के तहत 24 राज्यों में 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) घोषित किया गया है।[159] इनमें पांच मौजूदा जलमार्ग और 106 नए जलमार्ग शामिल हैं।[159] दिसंबर 2024 तक 26 को चालू कर दिया गया है।[160] बंदरगाह, जहाजरानी और

जलमार्ग मंत्रालय ने कमिटी को बताया था कि 63 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन्हें अलाभकारी माना गया है।[163]

- पिछले दशक (2014 से 2024) के दौरान 22% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही बढ़कर 133 मिलियन टन से अधिक हो गई है।[161] तीन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल यातायात में 75% हिस्सेदारी थी (तालिका 14)।[162] परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि भारत की माल ढुलाई में जलमार्गों की औसत हिस्सेदारी लगभग 2% है।[163] उसने यह भी कहा था कि अंतर्देशीय जलमार्ग के प्रयोग में संदेह के कई कारण हैं, जैसे: (i) अंतर्देशीय जल परिवहन की धीमी गति और विकास, (ii) खराब आंतरिक कनेक्टिविटी, और (iii) जहाजों और उपकरणों की उच्च लागत।[163]

तालिका 14: 2023-24 में अंतर्देशीय जल के माध्यम से माल ढुलाई में तीन राष्ट्रीय जलमार्गों की 75% हिस्सेदारी

जलमार्ग	कवर किया गया क्षेत्र	राज्य	2023-24 में यातायात (मिलियन टन में)	कुल यातायात में हिस्सा
एनडब्ल्यू-91	शास्त्री नदी - जयगढ़ क्रीक प्रणाली	महाराष्ट्र	37	28%
एनडब्ल्यू-100	तापी नदी	महाराष्ट्र, गुजरात	31	24%
एनडब्ल्यू-10	अंबा नदी	महाराष्ट्र	30	23%
एनडब्ल्यू-1	गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया-इलाहाबाद)	उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल	13	10%
एनडब्ल्यू-97	सुंदरबन जलमार्ग	पश्चिम बंगाल	5	4%
एनडब्ल्यू-4	कृष्णा गोदावरी नदी प्रणाली	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दूचेरी और महाराष्ट्र	4	3%

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 4341, लोकसभा, बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, 20 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

- मार्च 2023 तक कुल माल ढुलाई गतिशीलता (फ्रेट मोबिलिटी) में अंतर्देशीय जलमार्गों की हिस्सेदारी 2% थी।[164] सरकार 2030 तक इस हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाने का इरादा रखती है।[164] मोडल शेयर बढ़ाने के प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) जलपथ का विकास, (ii) रोल-ऑन, रोल-ऑफ सेवाओं को बढ़ावा देना, (iii) मल्टी-मोडल टर्मिनल्स का निर्माण, और (iv) अंतर्देशीय जहाज ऑपरेटरों द्वारा कार्गो और यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करना।[164]
- 2016 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 20 जलमार्गों को एनडब्ल्यू घोषित किया गया था।[165] इसमें 19 नए जलमार्ग और एक मौजूदा जलमार्ग (एनडब्ल्यू-2) शामिल हैं। वर्तमान में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 20 एनडब्ल्यू में से केवल एक जलमार्ग, यानी, एनडब्ल्यू-2, चालू है।[163] 2023 तक असम में स्थित चार राष्ट्रीय जलमार्गों को व्यवहार्य माना गया है।[163] वर्तमान में 80 एमटीपीए कार्गो मुख्य रूप से रेल या सड़क के माध्यम से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में और उसके भीतर परिवहन किया जाता है।[163] परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए एनडब्ल्यू-2 को मल्टी-मोडल टर्मिनल के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था।[163]

ग्रामीण सड़क की कनेक्टिविटी: *सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 3,80,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है।*

- ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शुरू की गई थी। जनवरी 2025 तक योजना के तहत 8.17 लाख किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 7.7 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण (94%) किया जा चुका है।[166]

तालिका 15: पीएमजीएसवाई के तहत प्रगति

योजना	उद्देश्य	अंतिम तिथि	स्वीकृत सड़क की लंबाई (किमी में)	पूर्ण हुई सड़क की लंबाई (किमी में)	पूर्णता दर (%)
पीएमजीएसवाई-I	मैदानी इलाकों में 500 लोगों से अधिक और उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 लोगों से अधिक आबादी वाली बस्तियों को जोड़ना।	सितंबर 2022*	6,44,872	6,24,622	97
पीएमजीएसवाई-II	मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 50,000 किमी सड़कों को अपग्रेड करना।	सितंबर 2022*	49,795	49,026	98
पीएमजीएसवाई-III	ग्रामीण संपर्कों के माध्यम से 1.2 लाख किमी सड़क मार्गों को संघटित करना।	मार्च 2025	1,21,928	88,068	72
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	9 राज्यों में वामपंथी अतिवाद से सर्वाधिक प्रभावित 44 जिलों और आसपास के कुछ जिलों में सड़क संपर्क में सुधार करना।	मार्च 2023*	12,228	9,334	76

नोट: *पीएमजीएसवाई-I के लिए लक्ष्य शुरू में मार्च 2019 था और पीएमजीएसवाई -II और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के लिए यह मार्च 2020 था। स्रोत: पीएम-जीएसवाई डैशबोर्ड, 10 जनवरी, 2024 को एक्सेस; पीआरएस।

- ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत परियोजनाओं के पूरा होने में देरी दर्ज की।[167] मंत्रालय ने लक्ष्यों को पूरा करने में देरी के कई कारण बताए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कठिन भूभाग और कानून व्यवस्था के मुद्दे, (ii) लॉजिस्टिकल और आपूर्ति संबंधी चुनौतियां, और (iii) राज्यों द्वारा धनराशि जारी करने में देरी।[167] कमिटी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को योजना के तहत बस्तियों की सूची को अपडेट करने का सुझाव दिया। ऐसा इसलिए है, क्योंकि पात्रता के लिए उपयोग किए जाने वाले आंकड़े 2001 की जनगणना पर आधारित हैं, जिसके कारण कुछ बस्तियां असंबद्ध (अनकनेक्टेड) रह सकती हैं।[167]
- पात्र असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 2024 में पीएमजीएसवाई-IV को मंजूरी दी गई थी।[168] पीएमजीएसवाई-IV के तहत, सरकार ने 25,000 असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को 62,500 किलोमीटर लंबी बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।[168] यह योजना 70,125 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 2028-29 तक लागू की जाएगी।[168]

पर्यावरण एवं ऊर्जा

जलवायु लक्ष्य: *देश अपने जलवायु संबंधी लक्ष्यों को तय समय से काफी पहले हासिल कर रहा है।*

- 2015 में भारत ने युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अंग के रूप में कुछ लक्ष्य तय किए थे।[169] इनमें बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म क्षमता बढ़ाने, कार्बन सिंक बढ़ाने और जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के लक्ष्य शामिल हैं। तालिका 17 इन लक्ष्यों और उनसे संबंधित उपलब्धियों को सूचीबद्ध करती है। अगस्त 2022 में भारत ने इनमें से कुछ लक्ष्यों को संशोधित किया।[170]

तालिका 16: क्षेत्र के अनुसार भारत का कुल उत्सर्जन (मिलियन टन CO2 समतुल्य में)

क्षेत्र	2010		2020	
	राशि	% हिस्सा	राशि	% हिस्सा
ऊर्जा	1,510	71%	2,238	76%
कृषि	390	18%	406	14%
औद्योगिक प्रक्रियाएं और उत्पाद उपयोग	172	8%	239	8%
कचरा	65	3%	76	2%
उपरोक्त क्षेत्रों से कुल उत्सर्जन	**2,137**	**-**	**2,959**	**-**

- इसके अलावा उसने निम्नलिखित लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं: (i) 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की 500 GW स्थापित क्षमता प्राप्त करना, (ii) 2030 तक अक्षय स्रोतों से 50% बिजली की आवश्यकता को पूरा करना, (iii) 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी लाना, और (iv) 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना।[171] बिजली उत्पादन और स्थापित क्षमता पर अधिक जानकारी के लिए अगला भाग देखें।

भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी	-253	-	-522	-
शुद्ध उत्सर्जन	**1,884**	**-**	**2,437**	**-**

स्रोत: युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2024 की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; पीआरएस।

तालिका 17: युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत भारत के प्रमुख लक्ष्य

2015 में निर्धारित लक्ष्य	स्थिति	अगस्त 2022 तक संशोधित लक्ष्य
उत्सर्जन सघटता में कमी: 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 33% से 35% तक कम करना	2005 और 2020 के बीच उत्सर्जन की तीव्रता 36% कम हो गई	2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना।
गैर-जीवाश्म क्षमता बढ़ाना: बिजली उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 2030 तक 40% तक बढ़ाना	अक्टूबर 2024 में स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 47% थी	2030 तक बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 50% तक बढ़ाना
कार्बन सिंक बनाना: 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना	2005 और 2021 के बीच 2.3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया	पहले जैसा ही

स्रोत: युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2024 की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; पीआरएस।

अक्षय ऊर्जा: *सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षमताओं को भी कई गुना बढ़ाया है। शुद्ध शून्य यानी नेट ज़ीरो की दिशा में हमारी पहल कई देशों के लिए प्रेरणा है।*

- अपनी जलवायु-संबंधी प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में 2030 तक भारत का लक्ष्य निम्नलिखित हासिल करना है: (i) 500 GW गैर-जीवाश्म उत्पादन क्षमता, (ii) अपनी बिजली की आवश्यकता का कम से कम 50% अक्षय स्रोतों से पूरा करना।[172] दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता 209 GW थी, जो कुल स्थापित क्षमता (462 GW) का 45% है।[173] इसमें सौर, पवन, पनबिजली और अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाएं जैसे स्रोत शामिल हैं। हालांकि सौर और पवन ऊर्जा प्रकृति में अनिरंतर होती है और थर्मल और पनबिजली की तुलना में इसकी क्षमता का उपयोग कम होता है। इसकी तुलना में 2013 में अक्षय ऊर्जा क्षमता कुल क्षमता का 12% थी।[174] 2023-24 में 21% बिजली उत्पादन अक्षय स्रोतों से था।[175]

तालिका 18: स्रोत आधारित स्थापित क्षमता और उत्पादन में हिस्सेदारी

स्रोत	दिसंबर 2024 तक स्थापित क्षमता		2023-24 में उत्पादन में हिस्सेदारी
	GW में	% हिस्सा	
कोयला	219	47%	75%
सौर	98	21%	7%
हाइड्रो	52	11%	9%
हवा	48	10%	5%
तेल एवं गैस	25	5%	2%
जैव शक्ति	11	2%	1%
नाभिकीय	8	2%	3%

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण; भारत का जलवायु और ऊर्जा डैशबोर्ड, 20 जनवरी, 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

- सरकार ने 2022 तक 100 GW सौर और 60 GW पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।[176] दिसंबर 2024 तक सौर की स्थापित क्षमता 98 GW और पवन की 48 GW थी।[173]

रूफटॉप सोलर: *पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। प्रति परिवार 78,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत एक करोड़ से अधिक परिवार पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। छत पर सोलर इंस्टॉलेशन करने वाले घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है।*

- पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 में 75,021 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ शुरू की गई थी।[177] यह योजना आवासीय उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर लगाने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसका लक्ष्य एक करोड़ रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन को प्रोत्साहित करके 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में 30 GW सौर क्षमता जोड़ना है।[178] दिसंबर 2024 तक योजना के लिए 26 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और 5.5 लाख इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं।[179]
- पूर्व रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का लक्ष्य 2022 के अंत तक 40 GW सौर क्षमता जोड़ने का था।[180] दिसंबर 2024 तक 16 GW रूफटॉप सोलर क्षमता जोड़ी गई है।[181] इस योजना को पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शामिल कर दिया गया है।[178]

महिलाओं के लिए किफायती गैस सिलिंडर: *मुफ्त राशन और किफायती गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने वाली योजनाओं से भी महिलाओं को काफी लाभ हो रहा है।*

- देश भर के गरीब परिवारों को खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की सुविधा प्रदान करने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। इस योजना में मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था।[182] शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए उज्ज्वला 2.0 को 1.6 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था।[183] पीएमयूवाई चरण-2 में प्रवासी परिवारों पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया।[184] इसके बाद सरकार ने 2023-24 और 2025-26 के बीच तीन वर्षों में 75 लाख और एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है।[185] इससे पीएमयूवाई लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी।[186] अगस्त 2024 तक 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं।[187]
- पब्लिक एकाउंट्स कमिटी (2024) ने पीएमयूवाई के कार्यान्वयन में कुछ समस्याओं पर प्रकाश डाला। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कनेक्शन प्रदान करने में देरी, (ii) डुप्लिकेट कनेक्शन जारी करना, (iii) परिवार के पुरुष सदस्यों को अपात्र कनेक्शन जारी करना।[188] पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा कि पीएमयूवाई के तहत जारी एलपीजी सिलेंडर की वर्तमान रीफिल दर 3.95 प्रति वर्ष है, जो गैर-पीएमयूवाई एलपीजी सिलेंडर (6.5) से कम है।[189] पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (2016) की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एलपीजी कनेक्शन तक पहुंच की प्रमुख बाधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सिक्योरिटी डिपॉजिट/गैस स्टोव की कीमत सहित उच्च प्रारंभिक लागत, (ii) सिलेंडर की उच्च आवर्ती लागत , और (iii) जलावन लकड़ी की आसान उपलब्धता। [190]

श्रम एवं रोजगार

सामाजिक सुरक्षा: *सरकार श्रमिकों के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत कर रही है। डिजिटल इंडिया और डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से दुर्घटना और जीवन बीमा का दायरा बढ़ाया जा रहा है।*

- सितंबर 2020 में संसद ने सामाजिक सुरक्षा संहिता पारित की।[191] इसमें नौ श्रम कानूनों को समाहित किया गया है जोकि विभिन्न प्रकार के श्रम करने वाले श्रमिकों से संबंधित थे।[192] यह संहिता असंगठित श्रमिकों, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है।[191] संहिता अभी तक लागू नहीं हुई है।[193] चूंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य, दोनों को संहिता के तहत नियम बनाने का अधिकार है।[194] केंद्र ने इस संहिता के तहत नियमों का ड्राफ्ट पहले ही प्रकाशित कर दिया है।[195] नवंबर 2024 तक 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इस संहिता के तहत अड्राफ्ट नियम प्रकाशित किए हैं।[193]

- 2019 में केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) शुरू की।[196] इसके तहत 2020-21 से 2022-23 के बीच तीन करोड़ लाभार्थियों के पंजीकरण का संचयी लक्ष्य था।[197] दिसंबर 2024 तक 51 लाख लाभार्थी इस योजना के तहत नामांकित हैं।[196] योजना के तहत कम नामांकन के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) लाभार्थियों द्वारा दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता, और (ii) राज्यों में अलग पेंशन योजनाओं की मौजूदगी, जैसे कि राजस्थान और हरियाणा, जहां लाभार्थियों को कोई योगदान नहीं देना पड़ता है।[197]
- मई 2015 में केंद्र सरकार ने भारत में जीवन और दुर्घटना बीमा तक पहुंच बढ़ाने के लिए दो योजनाएं शुरू कीं (तालिका 19)।[198]

तालिका 19: जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा कवरेज योजनाओं पर एक नजर

योजना	पात्रता	लाभ	वार्षिक प्रीमियम	कुल नामांकन (करोड़ में)	
				2017-18	2023-24
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	18-50 वर्ष आयु वर्ग के सभी व्यक्तिगत बैंक खाता/डाकघर खाताधारक	दो लाख रुपए का वार्षिक जीवन बीमा कवर	436 रुपए (पॉलिसी वर्ष 2023-24 के लिए)	3.2	18.6
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	18-70 वर्ष आयु वर्ग के सभी व्यक्तिगत बैंक खाता/डाकघर खाताधारक	दो लाख रुपए तक का वार्षिक दुर्घटना/विकलांगता कवर	20 रुपए	10	41.3

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 2350, लोकसभा, वित्त मंत्रालय, 18 दिसंबर, 2023; पीआरएस।

- इरडाई के अनुसार, भारत में जीवन बीमा की पहुंच 2021-22 में 3.2% से घटकर 2023-24 में 2.8% हो गई।[199] बीमा पैठ को बीमा प्रीमियम और जीडीपी के अनुपात के रूप में मापा जाता है। इस अवधि के दौरान गैर-जीवन बीमा पैठ लगभग 1% रही।[199] इरडाई के अनुसार, जबकि जीवन बीमा पैठ विश्व औसत (2023 में 2.9%) के बराबर थी, गैर-जीवन बीमा पैठ विश्व औसत (4.2) से काफी कम थी (2023 में %)।[199]
- भारत में कम बीमा पहुंच के कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) निम्न उपभोक्ता प्राथमिकता, (ii) अप्रयुक्त ग्रामीण बाजार, और (iii) वितरण चैनलों में बाधाएं।[200] उदाहरण के लिए, कई बीमा एजेंट अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। नतीजतन, लोग बिना किसी एजेंट के रह जाते हैं और पॉलिसी की कोई निगरानी नहीं होती है।[201] अन्य बाधाएं इस प्रकार हैं: (i) डिजिटल विभाजन, (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा एजेंटों/मध्यस्थों का कमजोर नेटवर्क।[202]

रेखाचित्र 13: भारत में बीमा प्रवेश में 2021-22 और 2023-24 के बीच गिरावट (% में)

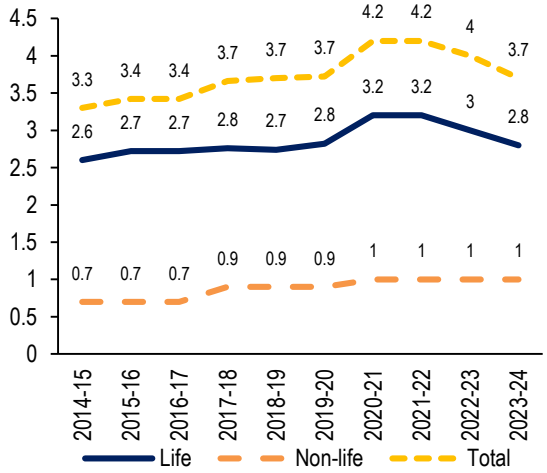

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण; पीआरएस।

- डाक विभाग बीमा सेवाएं प्रदान करता है।[203] इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और (ii) ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई)।[203] 2020-21 में, 2.9 लाख डाक जीवन बीमा और लगभग सात लाख ग्रामीण डाक बीमा पॉलिसियां जारी की गईं।[204]

- 2024 में विभाग ने एक समूह दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की।[205,206] यह 10 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज प्रदान करती है।[206] इसके तहत आकस्मिक मृत्यु और अस्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में तथा अस्पताल में भर्ती होने पर प्रत्येक दिन एक निश्चित राशि के प्रावधान, जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं।[206]

फुटपाथी दुकानदारों को ऋण: *पीएम-स्वनिधि का दायरा बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में रेहड़ी-पटरी वालों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।*

- आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित फुटपाथी दुकानदारों की सहायता के लिए जून 2020 में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) लॉन्च की।[207] इस योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।[208] यह योजना फुटपाथी दुकानदारों को 7% वार्षिक ब्याज सबसिडी के साथ कोलेट्रल-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है।[209] प्रारंभ में 10,000 रुपए का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है।[209] पिछले ऋण के पुनर्भुगतान पर दो और किस्तें प्रदान की जाती हैं।[209] 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले काम करने वाले सभी शहरी फुटपाथी दुकानदार पात्र लाभार्थी हैं।[209] लाभार्थियों की पहचान शहरी स्थानीय निकायों या टाउन वेंडिंग समितियों द्वारा की जाती है।[209] शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमा में आसपास के अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के फुटपाथी दुकानदारों पर भी विचार किया जा सकता है।[210]
- जनवरी 2025 तक योजना के तहत 1.15 करोड़ ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 99 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं (85%)।[211] यह 14,328 करोड़ रुपए के ऋणों की मंजूरी के बराबर है।[211] स्वीकृत राशि में से 13,737 करोड़ रुपए (96%) वितरित किए जा चुके हैं।[211] लगभग 42.6 लाख ऋण चुकाए गए हैं।[211]

तालिका 20: 29 जनवरी, 2025 तक पीएम-स्वनिधि के तहत वितरित ऋणों की संख्या (लाख में)

ऋण अवधि	पात्रता	स्वीकृत	वितरित	पात्र आवेदकों के % के रूप में वितरित ऋण	चुकाए गए ऋणों की संख्या
पहली अवधि (10,000 रुपए)	79	69.3	68	86%	35
दूसरी अवधि (20,000 रुपए)	29	24.2	23	79%	7
तीसरी अवधि (50,000 रुपए)	6.4	5	4.7	73%	-*

नोट: * तीसरी किस्त में 1,311 ऋण चुकाए गए हैं, जैसा कि अंतिम बार 29 जनवरी, 2025 को एक्सेस किया गया था।
स्रोत: पीएम-स्वनिधि वेबसाइट और डैशबोर्ड, जैसा कि 29 जनवरी, 2025 को एक्सेस किया गया; पीआरएस।

आवासन

महिलाओं के लिए आवास: *पिछले 10 वर्षों के दौरान 4 करोड़ पीएम आवास घरों में से अधिकांश महिला लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। 3 करोड़ नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनमें से अधिकांश आवास महिला लाभार्थियों को आवंटित किए जाएंगे।*

- 2015 में इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और शहरी (पीएमएवाई-यू) क्षेत्रों में कुछ समूहों को किफायती आवास तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। योजनाओं को मूल रूप से 2022 तक जारी रखने का इरादा था।[212] उन्हें दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।[212,213] योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत बनाए गए घर या तो परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त नाम पर हैं।[214]
- 27 जनवरी, 2025 तक पीएमएवाई-यू के तहत 1.2 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है।[215] इनमें से लगभग 90 लाख घर पूरे हो चुके हैं (75%)।[216] अगस्त 2024 तक पीएमएवाई-यू के तहत लगभग 50 लाख घर महिलाओं के स्वामित्व वाले थे।[217]

तालिका 21: पीएमएवाई-यू के घटकों के तहत भौतिक प्रगति (27 जनवरी, 2025 तक)[218]

योजना	उद्देश्य	पूरा	निर्माणाधीन	शुरू होना बाकी
इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)	पात्र झुग्गीवासियों को आवास उपलब्ध कराना	1,68,924	55,385	71,289
साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लाभार्थियों को पक्के घर (सार्वजनिक/निजी एजेंसी द्वारा निर्मित) के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना	9,32,897	3,55,292	2,77,029
क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना (सीएलएसएस)	निम्न आय समूह (एलआईजी), मध्यम आय समूह (एमआईजी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को गृह ऋण पर ब्याज सबसिडी प्रदान करना	25,04,220	-	-
लाभार्थी आधारित निर्माण/संवर्द्धन (बीएलसी)	पात्र ईडब्ल्यूएस परिवारों को या तो नया घर बनाने या मौजूदा घरों को बढ़ाने के लिए सहायता देना	50,77,648	17,54,919	6,59,567

स्रोत: पीएमएवाई-यू डैशबोर्ड 28 जनवरी, 2025 को एक्सेस; पीआरएस।

- आवासन एवं शहरी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा कि 2022 तक 14.4 लाख घरों की मांग के मुकाबले, आईएसएसआर घटक के तहत केवल 4.3 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी।[219] इसके अलावा कमिटी ने कहा कि आईएसएसआर और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (ईडब्ल्यूएस के लिए फ्लैट) घटकों के तहत पूरे किए गए 7% घर बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण खाली हैं।[219]
- पीएमएवाई-जी के तहत सरकार ने 3.7 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा था।[220] जनवरी 2025 तक 2.7 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं (73%)।[220] जून 2024 तक निर्मित घरों में से 77 लाख (26%) महिलाओं के एकमात्र स्वामित्व वाले थे।[221]
- पीएमएवाई-जी के तहत, अगर किसी लाभार्थी के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।[222] जुलाई 2023 तक लगभग 2.9 लाख भूमिहीन लाभार्थी घर बनाने के लिए भूमि आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे थे।[222] ग्रामीण विकास से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने सुझाव दिया था कि मंत्रालय इन लाभार्थियों के लिए भूमि सुनिश्चित करने और बहुमंजिला आवास जैसे वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करे।[222]
- अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों में तीन करोड़ अतिरिक्त घरों (पीएमएवाई-जी के तहत दो करोड़ और पीएमएवाई-यू के तहत एक करोड़) को मंजूरी दी।[223,224] इन योजनाओं पर अनुमानित परिव्यय 2.3 लाख करोड़ रुपए है।[223]

[1] Address by the President of India to the Joint Sitting of two houses of Parliament, Office of the President of India, June 27, 2024, https://www.presidentofindia.gov.in/sites/default/files/2023-06/speech_english.pdf.
[2] "India's Economic Renaissance: A New Era of Global Leadership" Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, October 16, 2024 https://pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=153288&ModuleId+=+2&reg=3&lang=1.
[3] GDP current prices, International Monetary Fund, 2024, as accessed on January 29, 2025, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.
[4] First Advanced Estimates of Gross Domestic Product for 2024-25, Ministry of Statistics and Program Implementation, January 7, 2025 https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/PR_NAD_07012025_0.pdf.
[5] "Public Sector Banks: A Resurgent Force" Press Information Bureau, Ministry of Finance, December 15, 2024 https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153573&ModuleId=3&reg=3&lang=1.
[6] Operation and Performance of Commercial Banks, Trend and Progress of Banking in India 2023-24, Reserve Bank of India, December 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/06OPERATIONS2612243AA56D31B20244688A4C99E91D57A247.PDF.
[7] Bank Group wise, population group wise Deposit details of SCBs (BSR-2), Database of Indian Economy, Reserve Bank of India, as accessed on January 28, 2024, https://data.rbi.org.in/BOE/OpenDocument/2409211840/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?logonSuccessful=true&shareId=2.
[8] "Banking Statistics I (Harmonised Definitions)" Reserve Bank of India, 2023, https://rbi.org.in/scripts/DataDefinition.aspx#BankingStatisticsI.

[9] Operation and Performance of Commercial Banks, Trend and Progress of Banking in India 2017-18, Reserve Bank of India, December 2018, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/CHAPTER043846D5694CD4400083553D7CBEC9C2D6.PDF.
[10] Banking Analytics, Ministry of Finance https://financialservices.gov.in/beta/en/analytics-banking.
[11] Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, Ministry of Finance https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2154.
[12] Insolvency and Bankruptcy News, Insolvency and Bankruptcy Board of India, July-September 2024, https://ibbi.gov.in/uploads/publication/edc044b410d37f0fd22cbe07a74665f3.pdf.
[13] FAQs, Insolvency and Bankruptcy Board of India, as accessed on January 20, 2025, https://ibbi.gov.in/uploads/faqs/CIRPFAQs%20Final2408.pdf.
[14] Report No 32: Implementation of Insolvency and Bankruptcy Code- Pitfalls and Solutions, Standing Committee on Finance, Lok Sabha, August 2021, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Finance/17_Finance_32.pdf?source=loksabhadocs.
[15] The Central Goods and Services Tax Act, 2017, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2017/Central%20GST%20Act,%202017.pdf.
[16] "Second highest monthly Gross GST Revenue collection in March at ₹1.78 lakh crore; Records 11.5% y-o-y growth (18.4% on net basis)", Press Information Bureau, Ministry of Finance, April 1, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2016802.
[17] Report of 15th Finance Commission, "Finance Commission in Covid Times", 2020, https://finance.cg.gov.in/15%20Finance%20Commission/Report/XVFC-Complete_Report-E.pdf.
[18] Volume-I, Report of the 15th Finance Commission for 2021-26, February 2021, https://fincomindia.nic.in/writereaddata/html_en_files/fincom15/Reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf.
[19] "Defence exports touch record Rs 21,083 crore in FY 2023-24, an increase of 32.5% over last fiscal; Private sector contributes 60%, DPSUs - 40%", Press Information Bureau, Ministry of Defence, April 1, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2016818.
[20] "Defence Exports Rise 23 Times", Press Information Bureau, Ministry of Defence, May 21, 2023, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1928533.
[21] "Year-end review, 2024" Press Information Bureau, Ministry of Defence, December 26, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2088180#:~:text=Defence%20Budget,allocation%20of%20FY%202023%2D24.
[22] "Year-end review, 2023", Press Information Bureau, Ministry of Defence, December 22, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1989502.
[23] "Marching Towards Atmanirbharta: India's Defence Revolution", Press Information Bureau, Ministry of Defence, October 29, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2069090#:~:text=According%20to%20data%20from%20all,46%2C429%20crore%20in%202014%2D15.
[24] Report No. 37: Demands for Grants (2023-24), Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning, Standing Committee on Defence, Lok Sabha, March 21, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/17_Defence_37.pdf?source=loksabhadocs.
[25] Unstarred Question No. 3013, "Budget Allocation for Defence Sector", Lok Sabha, Ministry of Defence, August 9, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU3013_R0dlbY.pdf?source=pqals.
[26] Products imported by Defence PSUs/SHQ, Department of Defence Production, Ministry of Defence, as accessed on January 28, 2025, https://srijandefence.gov.in/.
[27] "Splitting of OFB", Press Information Bureau, Ministry of Defence, November 29, 2021, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1776096.
[28] Report No. 4: Demand for Grants, Directorate of Ordnance (Coordination and Services) – New DPSUs, Defence Research and Development Organisation, Standing Committee on Defence, December 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Defence/18_Defence_4.pdf?source=loksabhadocs.
[29] Export Products, Defence Research & Development Organisation (DRDO), as accessed on January 20, 2025, https://www.drdo.gov.in/drdo/export-products?title=&sort_by=title&page=1.
[30] "One Rank One Pension (OROP) in India", Press Information Bureau, Ministry of Defence, November 7, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2071572.
[31] Unstarred Question No. 2579, "Development of North Eastern States", Rajya Sabha, Ministry of Development of North Eastern Region, March 23, 2023, https://sansad.in/getFile/annex/259/AU2579.pdf?source=pqars.
[32] Statement 11, Allocations for North-Eastern Areas, Expenditure Profile 2024-25, Union Budget, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat11.pdf.
[33] Report No. 8: Union Government (Civil) Compliance Audit Observations, Comptroller and Auditor General of India, 2024, https://cag.gov.in/en/audit-report/download/120358.
[34] Report No. 250: Action taken report on Demand for Grants (2023-24) of Ministry of Development of North Eastern Region, Standing Committee on Home Affairs, December 7, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/188/250_2023_12_12.pdf?source=rajyasabha.
[35] Strategy for New India @75, NITI Aayog, November 2018, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/Strategy_for_New_India_0.pdf.
[36] Annual Report 2023-24, Ministry of Home Affairs, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AnnualReport_27122024.pdf.
[37] The Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1527/1/a1958-28.pdf.
[38] "Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), 1958 in Northeastern States", Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, March 2022, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/mar/doc202233134101.pdf.
[39] Notification No. 378, Home Department, Government of Manipur, Manipur Gazette, March 30, 2024, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AFSPAManipur_29042024_0.pdf.
[40] S.O. 4921(E), Ministry of Home Affairs, The Gazette of India, November 14, 2024, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/ManipurPS_19112024.pdf.
[41] "90 more CAPF troops to be deployed in Manipur; total death toll of ethnic violence at 258: State security advisor", The New Indian Express, November 22, 2024, as accessed on January 29, 2025, https://www.newindianexpress.com/nation/2024/Nov/22/90-more-capf-troops-to-be-deployed-in-manipur-total-death-toll-of-ethnic-violence-at-258-state-security-advisor.
[42] Citizenship Amendment Bill, 2019, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2019/Citizenship%202019%20Bill%20Text.pdf
[43] Citizenship Amendment Rules, 2024, Ministry of Home Affairs, March 11, 2024, https://indiancitizenshiponline.nic.in/UserGuide/E_gazette_11032024.pdf.
[44] "First set of citizenship certificates after notification of Citizenship (Amendment) Rules, 2024 issued", Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, May 15, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2020671.

[45] "Process of granting citizenship certificates under the Citizenship (Amendment) Rules, 2024 commences in West Bengal", Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, May 29, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2022130#:~:text=The%20first%20set%20of%20Citizenship,on%2015th%20May%2C%202024
[46] The National Food Security Act, 2013, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2113/1/201320.pdf.
[47] "Serving Farmers and Saving Farming" Fifth Report, National Commission on Farmers, October 4, 2006, https://agriwelfare.gov.in/sites/default/files/NCF5%20Vol.-1%20%281%29.pdf.
[48] Unstarred Question No. 3553, "Uniform MSP for Foodgrain" Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3553_cRjHa9.pdf?source=pqals.
[49] Starred Question No. 301, "Average income of farmers" Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AS301_DNvhhc.pdf?source=pqals.
[50] "Income, Expenditure, Productive Assets and Indebtedness of Agricultural Households in India" NSS Round 70th, 2013, https://mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/nss_rep_576.pdf.
[51] "Land and livestock holdings of Households and Situation Assessment of Agricultural Households" NSS Round 77th, Ministry of Statistics and Programme Implementation, 2019, https://mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Report_587m_0.pdf.
[52] Unstarred Question No. 3572, "Categorisation of Farmers Under KISAN SAMMAN Pension Scheme" Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3572_uJEE74.pdf?source=pqals.
[53] Starred Question No. 205, "Benefits to SC/ST/OBC Farmers Under PM-KISAN Scheme" Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, December 10, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AS205_jgP2NW.pdf?source=pqals.
[54] Unstarred Question No. 2109, "Implementation of PM-KISAN", Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, August 9, 2024, https://sansad.in/getFile/annex/265/AU2109_YbH4cY.pdf?source=pqars#:~:text=Land%20seeding%20was%20made%20mandatory,April%202023%20%2D%20July%202023.
[55] PMKSY Website, as accessed on January 29, 2024, https://pmkisan.gov.in/.
[56] Starred Question No. 212, "National Mission on Edible Oil- Oil Seeds" Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 10, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AS212_LDDIUr.pdf?source=pqals.
[57] Unstarred Question No. 1329, "Initiatives to boost production of pulses", Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 3, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU1329_SquIRY.pdf?source=pqals.
[58] "Farmer Producer Organisations (FPOs)" Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 12, 2024, https://pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=148588&reg=3&lang=1.
[59] Unstarred Question No.2975, "MSMEs and FPO Schemes" Lok Sabha, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, December 12, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU2975_gCf9k8.pdf?source=pqals.
[60] About Primary Agriculture Cooperative Credit Societies (PACS), Ministry of Cooperation, as accessed on January 20, 2025, https://www.cooperation.gov.in/about-primary-agriculture-cooperative-credit-societies-pacs?utm.
[61] "Functional Primary Agricultural Cooperative Societies", Press Information Bureau, Ministry of Cooperation, November 27, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2077945#:~:text=As%20per%20data%20available%20on,PACS%20is%20enclosed%20as%20Annexure.
[62] Unstarred Question No 3620, "PACS as PMKSK", Lok Sabha, Ministry of Cooperation, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3620_nHjDJw.pdf?source=pqals.
[63] Starred Question No 117, "Onboarding of PACS on ERP Software" Lok Sabha, Ministry of Cooperation, December 3, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AS117_hbFvIT.pdf?source=pqals.
[64] Unstarred Question No. 3619, "Lakhpati DIDI" Lok Sabha, Ministry of Rural Development, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3619_ViZSvH.pdf?source=pqals.
[65] Starred Question No. 108, "KRISHI SAKHI Convergence Program" Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, July 30, 2024, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2977842/1/AS108_PW5Ubv.pdf.
[66] "NAMO Drone Didi Scheme" Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 17, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2085177.
[67] Unstarred Question No. 3536, "NAMO Drone Didi Scheme" Lok Sabha, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3536_OWPdJ0.pdf?source=pqals.

[68] "About Ayushman Bharat", Ministry of Health and Family Welfare, as accessed on January 7, 2025, https://nha.gov.in/PM-JAY#.
[69] Unstarred Question No. 2534, "Status of AB-PMJAY and ABDM in Tamil Nadu", Ministry of Health and Family Welfare, Rajya Sabha, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/annex/266/AU2534_ezNoMA.pdf?source=pqars.
[70] Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Dashboard, as accessed on January 7, 2025, National Health Authority, Ministry of Health and Family Welfare, https://dashboard.pmjay.gov.in/pmj/#/.
[71] National Health Profile 2023, 18th Issue, Ministry of Health and Family Welfare, https://cbhidghs.mohfw.gov.in/WriteReadData/l892s/Final_Central%20Bureau%20of%20Health%20Intelligene%20July%202024.pdf.
[72] Demand No. 46, Expenditure Budget, Ministry of Health and Family Welfare, Union Budget 2024-25, https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25(I)/doc/eb/sbe46.pdf.
[73] Report No. 151: Implementation of Ayushman Bharat", Standing Committee on Health and Family Welfare, December 19, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/14/187/151_2023_12_19.pdf?source=rajyasabha.
[74] Starred Question No. 24, Rajya Sabha, Ministry of Health and Family Welfare, December 5, 2023, https://sansad.in/getFile/annex/262/AS24.pdf?Sources=pqars.
[75] Report No. 11: Performance Audit of Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Comptroller and Auditor General of India, August 8 2023, https://cag.gov.in/en/audit-report/details/119060.
[76] National Health Accounts Estimates for India (2021-22), Ministry of Health and Family Welfare, https://nhsrcindia.org/sites/default/files/2024-09/NHA%202021-22.pdf.
[77] "Cabinet approves health coverage to all senior citizens of the age 70 years under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY)", Press Information Bureau, September 11, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2053883.
[78] "Ayushman Bharat: Vay Vandana Cards achieves Milestone", Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, November 18, 2024, https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153425&ModuleId=3&reg=3&lang=1.

[79] "Enrollment for Ayushman Vay Vandana Cards reaches 25 lakhs", Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, December 9, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2082288#:~:text=In%20a%20significant%20achievement%2C%20the,Minister%20on%2029%20October%2C%202024.
[80] "Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana" (PMBJP)", Department of Pharmaceuticals Ministry of Chemicals and Fertilisers, https://pharmaceuticals.gov.in/sites/default/files/Website%20updation%202022%20PMBJP-1.pdf.
[81] PMBI/06/Circular/74/2024-25, Circular by Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India, August 29, 2024, https://janaushadhi.gov.in/pdf/Circular%20Removal%20and%20Enhancement_30082024.pdf.
[82] "Pradhan Mantri Jan Aushadi Pariyojana achieved their target of Rs. 1000 crore in sales in FY 2023-24", Press Information Bureau, December 20, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1988675
[83] Unstarred Question No. 3023, "Jan Aushadhi Kendras", Ministry of Chemicals and Fertilizers, Lok Sabha, December 13, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3023_taxEnh.pdf?source=pqals.
[84] Report No. 17: Review of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadi Pariyojana (PMBJP), Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, March 2021, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/800849/1/17_Chemicals_And_Fertilizers_17.pdf.
[85] Annual Report 2023-24, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, https://pharmaceuticals.gov.in/sites/default/files/English%20version%20of%20Annual%20Report%202023-24.pdf.
[86] "Union Health Minister Shri J P Nadda lists out achievements of the Union Health Ministry in the First 100 Days of the New Government", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, September 20, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2057037#:~:text=in%202024%2D25.-,There%20has%20been%2098%25%20increase%20in%20medical%20colleges%20from%20387,medical%20colleges%20in%20the%20Country.
[87] Unstarred Question No. 851, "Medical Colleges in Chhattisgarh", Lok Sabha, Ministry of Health and Family Welfare, November 29, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU851_YLBE1z.pdf?source=pqals.
[88] Report No. 23: Medical Education and Health Care in the country, Ministry of Health and Family Welfare, Committee on Estimates (2017-2018), Lok Sabha, December 21, 2017, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Estimates/16_Estimates_23.pdf?source=loksabhadocs.
[89] Unstarred Question No. 851, "Medical Colleges in Chhattisgarh", Lok Sabha, Ministry of Health and Family Welfare, November 29, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU851_YLBE1z.pdf?source=pqals.
[90] Annual Report 2023-24, Ministry of Health and Family Welfare, https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report%202023%2024%20DoHFW%20English_0.pdf.
[91] Annual Report 2022-23, Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, Ministry of Health and Family Welfare, https://drive.google.com/file/d/1ujV53IkfeqgN0hhnS6_XvZQ0X9brVZX3/view
[92] "AIIMS in the country", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, February 11, 2020, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1602754.
[93] Report No. 10: Audit of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, Comptroller and Auditor General of India, Ministry of Health and Family Welfare, 2018, https://cag.gov.in/webroot/uploads/download_audit_report/2018/Report_No_10_of_2018_-_Performance_Audit_on_Pradhan_Mantri_Swasthya_Suraksha_Yojana_in_Ministry_of_Health_and_Family_Welfare.pdf
[94] Report No. 157 of the Standing Committee on Health and Family Welfare, on "Quality of Medical Education in India", the Department of Health and Family Welfare, February 9, 2024, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/14/187/157_2024_2_19.pdf?source=rajyasabha.
[95] Unstarred Question No 996, "New Universities for Expansion of Higher Education in the Country" Ministry of Education, Rajya Sabha, December 12, 2024 https://sansad.in/getFile/annex/266/AU996_2Z8Ci7.pdf?source=pqars.
[96] All India Survey on Higher Education 2021-22, Ministry of Education, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s392049debbe566ca5782a3045cf300a3c/uploads/2024/02/20240719952688509.pdf.
[97] 348th Report, Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, March 28, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/167/348_2023_3_16.pdf?source=rajyasabha.
[98] "India Employment Report 2024: Youth employment, education and skills", International Labour Organisation, https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-08/India%20Employment%20-%20web_8%20April.pdf.
[99] Research and Development Statistic at a glance 2022-23, Ministry of Science and Technology, https://dst.gov.in/sites/default/files/R%26D%20Statistics%20at%20a%20Glance%2C%202022-23.pdf.
[100] Chapter 8: Transforming Science and Technology in India, Economic Survey of India 2017-18, Ministry of Finance, https://www.indiabudget.gov.in/budget2018-2019/economicsurvey2017-2018/pdf/119-130_Chapter_08_ENGLISH_Vol_01_2017-18.pdf.

[101] Unstarred Question No. 3857, "Higher education dropout due to language barrier", Ministry of Education, Rajya Sabha, April 6, 2022, https://sansad.in/getFile/annex/256/AU3857.pdf?source=pqars.
[102] The National Education Policy, 2020, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.
[103] The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, Ministry of Education, https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/20100?view_type=browse .
[104] The Jharkhand Competitive Examination (Measures for Control and Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2023 https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/jharkhand/2023/Act15of2023Jharkhand.pdf.
[105] The Uttarakhand Competitive Examination (Measures For Control And Prevention Of Unfair Means In Recruitment) Act 2023 https://highcourtofuttarakhand.gov.in/files/Competitive_Examination._(Measures_for_Control_and_Prevention_of_Unfair_Means_in_Recruitment)_Act,_2023.pdf.
[106] The Uttar Pradesh Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/uttar-pradesh/2024/Act8of2024UP.pdf.
[107] Poverty and Inequality Platform, World Bank, last accessed on January 28, 2025, https://pip.worldbank.org/country-profiles/IND.
[108] Global Multidimensional Poverty Index 2024, Poverty amid Conflict, United Nations Development Programme, https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdp-document/mpireport2024en.pdf.
[109] Multidimensional Poverty in India since 2005-06, Discussion Paper, NITI Aayog, United Nations Development Programme, January 12, 2024, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-01/MPI-22_NITI-Aayog20254.pdf.
[110] National Multidimensional Poverty Index, India, A Progress Review, NITI Aayog, 2023, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimentional-Poverty-Index-2023.pdf.

[111] "100 days of Modi 3.0: Empowering Lives", Press Release, Ministry of Information and Broadcasting, September 23, 2024, https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152175&ModuleId=3&reg=3&lang=1.
[112] Unstarred Question No. 488, "PM JANMAN Scheme", Lok Sabha, Ministry of Tribal Affairs, July 25, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU488_4bKzPg.pdf?source=pqals.
[113] Starred Question No. 201, "Empowerment of Persons with Disabilities", Lok Sabha, Ministry of Social Justice and Empowerment, August 6, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AS201_JQMYmG.pdf?source=pqals.
[114] "Revision of Scheme of Assistance to Persons with Disabilities for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP Scheme) during the period of 15th Finance Commission i.e. from 01.04.2022 to 31.03.2026", Office Memorandum, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, September 26, 2024, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3e58aea67b01fa747687f038dfde066f6/uploads/2024/09/2024092713558618 74.pdf.
[115] Frequently Asked Questions, ALIMCO, https://alimco.in/WriteReadData/CMS/Awareness.pdf.
[116] "10 Years Achievements of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities since 2014-15", https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3e58aea67b01fa747687f038dfde066f6/uploads/2024/07/20240702579676785.pdf.
[117] Unstarred Question No. 567, "Assistive Technologies for PwDs", Lok Sabha, Ministry of Social Justice and Empowerment, February 6, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1715/AU567.pdf?source=pqals.
[118] "Year End Review- 2023 of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Ministry of Social Justice & Empowerment)", Press Information Bureau, Ministry of Social Justice and Empowerment, December 27, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1990676.
[119] "Secretary (DEPwD) inaugurates 'Pradhan Mantri Divyasha Kendra' at National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities (NIEPVD), Dehradun", Press Information Bureau, Ministry of Social Justice and Empowerment, October 14, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2064757.
[120] Report No. 2: Demand for Grants of Ministry of Social Justice and Empowerment, Standing Committee on Social Justice and Empowerment, Lok Sabha, December 12, 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Social%20Justice%20&%20Empowerment/18_Social_Justice_And_Empowerment_2.pdf?source=loksabhadocs.
[121] Report on Logistics Cost in India, National Council of Applied Economic Research, 2023, https://dpiit.gov.in/sites/default/files/NCAER_Report_LogisticsCost2023_24January2024_0.pdf.
[122] The National Logistics Policy, 2022, Ministry of Commerce and Industry, https://dpiit.gov.in/sites/default/files/NationalLogisticsPolicy_2022_29September2022_0.pdf.
[123] World Bank, 2023 Logistics Performance Index, as accessed on January 20, 2025, https://lpi.worldbank.org/international/global.
[124] Unstarred Question No. 2088, Lok Sabha, "Logistics Cost" Ministry of Commerce and Industry, August 02, 2024 https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1712/AU2088.pdf?source=pqals.
[125] Production Linked Incentive (PLI) Schemes in India, Invest India, as accessed on January 20, 2025https://www.investindia.gov.in/production-linked-incentives-schemes-india.
[126] Speech by Nirmala Sitharaman, Minister of Finance, Budget 2022-23 https://www.indiabudget.gov.in/doc/bspeech/bs202223.pdf.
[127] Unstarred Question No. 3656, Lok Sabha, "Application Under PLI Scheme" Ministry of Commerce & Industry, December 17, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3656_lSj6wd.pdf?source=pqals.
[128] Unstarred Question No 2642, Lok Sabha, "Incentives to Develop Solar Industry" August 07, 2024, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2979888/1/AU2642_NCfNmo.pdf.
[129] India Semiconductor Mission, accesses January 15th 2025, https://ism.gov.in/about-semiconindia-programme.html.
[130] Unstarred Question No. 1513, Lok Sabha, "Import to Meet Semiconductor Demand" Ministry of Electronics and Information Technology, December 04, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU1513_M9dUq7.pdf?source=pqals.
[131] "Construction of Tata's semiconductor unit in Assam commences today", Press Information Bureau, Ministry of Electronics and Information Technology, August 03, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2041162.
[132] Unstarred Question No. 900, "Implementation of FAME-II India Scheme" Rajya Sabha, Ministry of Heavy Industries, February 9, 2024, https://sansad.in/getFile/annex/263/AU900.pdf?source=pqars.
[133] "Fame India Scheme", Press Information Bureau, Ministry of Heavy Industries, July 25, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1942506.
[134] Unstarred Question No 924, Lok Sabha, Ministry of Heavy Industries September 19, 2020, https://sansad.in/getFile/annex/252/AU924.pdf?source=pqars.
[135] "16.15 Lakh Electric Vehicles Incentivised Under FAME-II Scheme" Press Information Bureau, Ministry of Heavy Industries, January 02, 2025 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2089612.

[136] "National Green Hydrogen Mission" Press Information Bureau, Ministry of New and Renewable Energy, July 24, 2024 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2039091#:~:text=The%20National%20Green%20Hydrogen%20Mission%20has%20an%20outlay%20of%20%E2%82%B9,6%2C00%2C000%20jobs%20by%202030.
[137] Unstarred Question No 3760, Lok Sabha, "Progress of National Green Hydrogen Mission" Ministry of New and Renewable Energy, December 18, 2024 https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3760_7TWyFn.pdf?source=pqals.
[138] Unstarred Question No. 3760, Lok Sabha, Ministry of New and Renewable Energy, December 18, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3760_7TWyFn.pdf?source=pqals.
[139] About Startup India, Startup India, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/about-startup-india-initiative.html.
[140] "Startup Nation: India" Press Information Bureau, Ministry of Commerce & Industry; December 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2087835
[141] "Recognised startups create over 16.6 lakh direct jobs across more than 55 varied industries" Press Information Bureau, Ministry of Commerce & Industry; December 25, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2081538
[142] Report 182, Standing Committee on Commerce, Rajya Sabha, August 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/13/174/182_2024_1_10.pdf?source=rajyasabha.
[143] Unstarred Question No. 2916, Rajya Sabha, Ministry of Commerce and Industry, December 20, 2024, https://sansad.in/getFile/annex/266/AU2916_AnM2Us.pdf?source=pqars.
[144] "Fund of Funds for Start-ups Scheme", Website of SIDBI as accessed on January 28, 2024, https://web.archive.org/web/20250128173758/https://www.sidbivcf.in/en/funds/ffs.

[145] 'UDAN Manual', Ministry of Civil Aviation, November, 2021, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/migration/UDAN-Manual.pdf
[146] Handbook of Civil Aviation Statistics 2023-24, Directorate General of Civil Aviation, https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/?page=jsp/dgca/InventoryList/dataReports/aviationDataStatistics/handbookCivilAviation/HANDBOOK%202023-24%20Final%20Draft.pdf&mainundefined.
[147] "619 RCS Routes Operationalised as on 23.12.2024", News and Notifications, Airports Authority of India, https://www.aai.aero/sites/default/files/rcs_news_notifications/619%20RCS%20Routes%20Operationalised%20as%20on%2023.12.2024.pdf.
[148] "519 routes operationalised under RCS- UDAN Scheme including 53 tourism & 48 helicopter routes", Press Information Bureau, Ministry of Civil Aviation, February 8, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2004057.
[149] Unstarred Question No. 1721, "Airports under UDAN scheme", Lok Sabha, Ministry of Civil Aviation, August 1, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU1721_3HArBo.pdf?source=pqals.
[150] "Minister of Railways, Shri Piyush Goyal briefs Media about this High Speed Train Project", Press Information Bureau, Ministry of Railways, September 11, 2017, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=170676.
[151] Unstarred Question No. 1384, "Implementation of High-Speed Rail Projects", Rajya Sabha, Ministry of Railways, December 6, 2024, https://sansad.in/getFile/annex/266/AU1384_XawmtN.pdf?source=pqars.
[152] Project Summary, Mumbai Ahmedabad High Speed Rail Project, Infrastructure and Project Monitoring Decision, as accessed on January 13, 2025, http://www.cspm.gov.in/ocmstemp/PROJ_SUMMARY?prcd=N22000463&stat=O.
[153] "Year End Review 2024; Ministry of Road Transport and Highways", Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, January 9, 2025, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2091508.
[154] Unstarred Question No. 2333, "State-roads and highways notified as national highways", Rajya Sabha, Ministry of Road Transport and Highways, March 23, 2022, https://sansad.in/getFile/annex/256/AU2333.pdf?source=pqars.
[155] Unstarred Question No. 506, "upgradation of state highways to national highways", Lok Sabha, Ministry of Road Transport and Highways, November 28, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU506_aHs7aN.pdf?source=pqals.
[156] Unstarred Question No. 3947, "Construction of National Highways", Lok Sabha, Ministry of Road Transport and Highways, December 19, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3947_YSW4Lu.pdf?source=pqals.
[157] Annual Report 2022-23, National Highways Authority of India, https://nhai.gov.in/nhai/sites/default/files/2024-08/NHAI-Annual_Report_2022-23-English-30-05-24.pdf.
[158] 461st Flash Report on Central Sector Projects (Rs 150 crore and above), Ministry of Statistics and Programme Implementation, March, 2024, http://www.cspm.gov.in/English/flr/FR_mar_2024.pdf.
[159] "Domestic and Foreign Investment for Development of Waterways", Press Information Bureau, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, August 6, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2042030#:~:text=To%20promote%20Inland%20Water%20Transport,the%20National%20Waterways%20Act%2C%202016.
[160] Starred Question No. 266, "Freight transportation through inland waterways", Lok Sabha, Ministry of Ports, Shipping, and Waterways, December 13, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AS266_Ap4A9v.pdf?source=pqals#:~:text=(a)%20Significant%20progress%20has%20been,2014%20to%2026%20in%202024.
[161] "Shri Sarbananda Sonowal Reviews Inland Water Transport Projects at IWAI Headquarters", Press Information Bureau, Ministry of Ports, Shipping, and Waterways, June 25, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2028605.
[162] Unstarred Question No. 4341, "Cargo movement through national waterways", Lok Sabha, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, December 20, 2024
[163] 358th Report: Development and Expansion of Existing and New National Inland Waterways, Departmentally Related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism, and Culture, September 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/20/193/358_2023_9_11.pdf?source=rajyasabha.
[164] "Government intends to increase the share of Inland Water Transport (IWT) to 5% as per Maritime India Vision (MIV)-2030" Press Information Bureau, Ministry of Ports, Shipping, and Waterways, March 17, 2023, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1907994#:~:text=by%20PIB%20Delhi-,Inland%20Water%20Transport%20(IWT)%20is%20the%20most%20economical%20mode%20of,%2D1.
[165] North Eastern Waterways, Inland Waterways Authority of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, as accessed on January 13, 2025, https://iwai.nic.in/departments/north-east-region-cell/north-eastern-waterways.
[166] PM-GSY Rural Dashboard, Accessed on 10.01.2025, https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTA2NzM0ZjAtNjhmMS00ZWE1LWIzMTUtY2Y3MjRjZTk5ZWQyIiwidCI6IjliZjc5NjA5LWU0ZTgtNDdhZC1hYTUzLTI0NjQ2MTg1NTM4YyJ9&pageName=ReportSection6c3e4a4e09e5c16ec50c.
[167] Thirty Sixth Report on Action Taken on the Report on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (2023-24), Ministry of Rural Development, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_36.pdf?source=loksabhadocs.
[168] "Cabinet approves implementation of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - IV (PMGSY-IV) during FY 2024-25 to 2028-29" Press Information Bureau, Ministry of Rural Development, September 11, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2053894.
[169] Second Biennial Update Report to The United Nations Framework Convention on Climate Change, Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, 2018, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/INDIA%20SECOND%20BUR%20High%20Res.pdf.
[170] 'Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution to be communicated to the United Nations Framework Convention on Climate Change', Press Information Bureau, Cabinet, August 3, 2022, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1847812.
[171] "India's Stand at COP-26 ", Press Information Bureau, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, February 3, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1795071.
[172] "India's Stand at COP-26", Press Information Bureau, Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, February 3, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1795071.
[173] Executive Summary Report, December 2024, Central Electricity Authority, https://cea.nic.in/wp-content/uploads/executive/2024/12/Executive_Summary_Dec_2024_Pro.pdf.
[174] Annual Report, Central Electricity Authority, 2012-13 https://cea.nic.in/wp-content/uploads/2020/03/annual_report-2013.pdf
[175] India Energy Climate Dashboard, NITI Aayog, as accessed on January 28, 2025, https://iced.niti.gov.in/energy/electricity/generation/power-generation.

[176] Report No. 17: Action Plan for Achievement of 175 GW Renewable Energy Target, Standing Committee on Energy, 17th Lok Sabha, March 2021, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Energy/17_Energy_17.pdf?source=loksabhadocs.
[177] Press Information Bureau "Cabinet approves PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana for installing rooftop solar in One Crore households", https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2010133.
[178] Operational Guideline, PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojna, Ministry of New and Renewable Energy, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3716e1b8c6cd17b771da77391355749f3/uploads/2024/07/2024070217680354 84.pdf.
[179] "PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana" Press Information Bureau, Ministry of New and Renewable Energy, December 05, 2024 https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2081250&reg=3&lang=1.
[180] Annual Report 2023-24, Ministry of New and Renewable Energy, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3716e1b8c6cd17b771da77391355749f3/uploads/2024/10/20241014958242917.pdf.
[181] Physical Progress Dashboard, Ministry of New and Renewable Energy, January 20, 2025 https://mnre.gov.in/en/physical-progress/.
[182] PMUY Website, as accessed on January 18, 2024, https://www.pmuy.gov.in/about.html.
[183] "Features of PMUY" Press Information Bureau, Ministry of Petroleum & Natural Gas, August 10, 2023 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1947509.
[184] Starred Question No. 2900, "Pradhan Mantri Ujjwala Yojana in Tamil Nadu", Lok Sabha, Ministry of Petroleum and Natural Gas, August 8, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU2900_xyVX7A.pdf?source=pqals.
[185] Unstarred Question No. 680, Lok Sabha, Ministry of Petroleum and Natural Gas November 28, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU680_oGpb3I.pdf?source=pqals.
[186] Cabinet approves expansion of Ujjwala Yojana 75 lakh additional LPG connections to be released in 3 years, Press Information Bureau, Ministry of Petroleum and Natural Gas, September 13 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1957091#:~:text=It%20will%20take%20total%20number%20of%20PMUY%20beneficiaries%20to%2010.35%20crore&text=The%20Union%20Cabinet%2C%20chaired%20by,%2D24%20to%202025%2D26.
[187] Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Ministry of Petroleum and Natural Gas, as last accessed on January 7, 2025, https://pmuy.gov.in/.
[188] Report No. 130: Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Public Accounts Committee 2023-24, Lok Sabha, Ministry of Petroleum and Natural Gas, February 2024, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2976833/1/17_Public_Accounts_130.pdf.
[189] Report No. 1: Demand for Grant Analysis (2024-25), Standing Committee On Petroleum & Natural Gas (2024-25), December, 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Petroleum%20&%20Natural%20Gas/18_Petroleum_And_Natural_Gas_1.pdf?source=loksabhadocs .
[190] Assessment report: Primary survey on household cooking fuel usage and willingness to convert to LPG, Petroleum Planning & Analysis Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas, June 2016, https://ppac.gov.in/uploads/importantnews/1668081308_PrimarySurveyReportPPAC.pdf
[191] The Code on Social Security, 2020, https://prsindia.org/billtrack/the-code-on-social-security-2020.
[192] "Lok Sabha passes 3 Historic and path breaking Labour Codes", Press Release, Ministry of Labour and Employment, Press Information Bureau, September 22, 2020. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1657898.
[193] Chapter 8 – Unorganised Worker, Annual Report 2023-24, Ministry of Labour and Employment, https://labour.gov.in/sites/default/files/ar_2023_24_compressed.pdf.
[194] Entry No. 22, 23, 24, List III – Concurrent List, Constitution of India https://legislative.gov.in/constitution-of-india/.
[195] "Labour welfare and social security in the informal and gig economy", Press Release, Ministry of Labour and Employment, Press Information Bureau, November 25, 2024, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2076951#:~:text=As%20per%20available%20information%2C%2032,Conditions%20Code%2C%202020%2C%20respectively.
[196] Starred Question No. 191, "Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhaan scheme", Rajya Sabha, Ministry of Labour and Employment, December 2024, https://sansad.in/getFile/annex/266/AS191_8RDyFC.pdf?source=pqars.
[197] Report no. 41: Demand for Grants, Standing Committee on Labour, textiles and Skill Development, March 13, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Labour,%20Textiles%20and%20Skill%20Development/17_Labour_Textiles_and_Skill_Development_41.pdf?source=loksabhadocs.
[198] Unstarred Question No. 2350, Lok Sabha, Ministry of Finance, December 18, 2023, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1714/AU2350.pdf?source=pqals.
[199] Annual Report 2023-24, Insurance Regulatory and Development Authority of India, https://irdai.gov.in/document-detail?documentId=6436847.
[200] "Pre-launch Survey Report of Insurance Awareness Campaign", National Council of Applied Economic Research, Insurance Regulatory and Development Authority, January 2011, https://irdai.gov.in/documents/37343/1082836/INSURANCE_AWARENESS_insdie_report_final_for_mail.pdf/26d8fb2d-5ac9-9d71-3803-e7aaa6a99e38?version=1.0&t=1640596154328.

[201] Report of the Committee on Distribution Channels, Insurance Regulatory and Development Authority, https://irdai.gov.in/documents/37343/1369659/Report+of+the+Committee+on+Distribution+Channels.pdf/696d1bf4-9572-f047-0448-11d1593e1954?version=1.1&t=1662752508493
[202] "Increasing General Insurance Penetration in rural areas with special focus on agriculture and allied activities through the concept of a Model Insured Village", Discussion Paper, Insurance Regulatory and Development Authority, May 3, 2021, https://irdai.gov.in/document-detail?documentId=397557.
[203] Annual Report 2020-21, Department of Posts, Ministry of Communications, https://www.indiapost.gov.in/VAS/DOP_PDFFiles/AnnualReportEng2020-21.pdf.
[204] Unstarred Question No. 1940, "India Post Banking and Insurance Services", Rajya Sabha, Ministry of Communications, August 5, 2021, https://sansad.in/getFile/annex/254/AU1940.pdf?source=pqars.
[205] Chapter C – Financial Services, India Post Payments Bank, Annual Report 2023-24, Department of Posts, Ministry of Communications, https://www.indiapost.gov.in/VAS/DOP_PDFFiles/AR%202023-24_Eng%20of%20DoP.pdf.
[206] Group Accident Insurance (Group Accident Guard), India Post Payments Bank, as accessed on January 7, 2025, https://ippbonline.com/web/ippb/tagic-group-accident-insurance.
[207] "PM SVANidhi Scheme", Ministry of Housing and Urban Affairs, August 7, 2023, Press Information Bureau, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1946307.
[208] "Extension of PM SVANidhi Scheme", Ministry of Housing and Urban Affairs, December 8, 2022, Press Information Bureau, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1881759.

[209] "PM SVANidhi 2.0- Revised guidelines of the Scheme w.e.f. 01.06.2022", MSME Department, Bank of Maharashtra, PM SVANidhi, Ministry of Housing and Urban Affairs, June 16, 2022, https://www.pmsvanidhi.mohua.gov.in/Default/ViewFile/?id=Bank+of+Maharastra.pdf&path=MiscFiles.
[210] "PM Svanidhi Scheme", Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, August 7, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1946307 .
[211] PM-SVANidhi Dashboard, as accessed on January 29, 2025, https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/PMSDashboard.
[212] "Houses for all under Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin," December 13, 2022, Press Information Bureau, Ministry of Rural Development, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1883183
[213] "Cabinet approves continuation of Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) - "Housing for All" Mission up to 31st December 2024", August 10, 2022, Press Information Bureau, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1850679
[214] PMAY (URBAN), Ministry of Housing and Urban Affairs, last accessed on January 28, 2025, http://pmay-urban.gov.in/about.
[215] Details of Pradhan Mantri Awas Yojana, Press Information Bureau, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/dec/doc20241210468501.pdf.
[216] PMAY-Urban progress, last accessed on January 28, 2025, https://pmay-urban.gov.in/.
[217] "Houses Registered in Name of Women Under PMAY-U", Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, August 5, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2041569.
[218] PMAY(U) Achievement, as on January 27, 2025, https://pmay-urban.gov.in/uploads/progress-pdfs/679757c6a54cb-web.pdf.
[219] Report No. 20: Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Seventeenth Report Evaluation of Implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban), Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Lok Sabha, December 8, 2023, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2963548/1/17_Housing_and_Urban_Affairs_20.pdf.
[220] Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin dashboard, Ministry of Rural Development, last accessed on January 28, 2025, https://dashboard.rural.nic.in/dashboardnew/pmayg.aspx.
[221] "Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)", Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, June 13, 2024, https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151895&ModuleId=3&reg=3&lang=1.
[222] Report No. 33 of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (2022-23), July 27, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_and_Panchayati_Raj_33.pdf?source=loksabhadocs.
[223] "Cabinet approves Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 Scheme", Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, August 9, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2043924.
[224] Unstarred Question No. 1412, "Construction of Houses under PM Awaas Yojana Gramin", Rajya Sabha, Ministry of Rural Development, December 6, 2024, https://sansad.in/getFile/annex/266/AU1412_kMMdMt.pdf?source=pqars.

स्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई है। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी की मूल रिपोर्ट से इसकी पुष्टि की जा सकती है।